वर्ष 12 • अंक 272 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 2 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 4

घटा ईरान से कच्चे तेल का आयात

जनरल विपिन रावत ▶▶ पृष्ठ 12

हम स्वयं को राजनीति से रखते हैं अलग

डॉलर रु. 71.20 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 79.90 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 38962 ▼ 121 रुपये | सेंसेक्स 41306.00 ▲ 52.30 | निफ्टी 12182.50 ▲ 14.00 | निफ्टी फ्यूचर्स 12243.80 ▲ 61.30 | ब्रेंट क्रूड 66.30 डॉलर ▼ 0.10 डॉलर

एक नज़र

चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष संभव

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को कहा कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष हो सकता है। इसरो ने साथ ही महत्त्वकांक्षी गगनयान कार्यक्रम के लिए भी 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया है और जल्द ही रूस में उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसरो प्रमुख के सिवन कहा कि चंद्रयान-3 मिशन से संबंधित सभी गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 और मिशन गगनयान का काम एक साथ चल रहा है। वैसे एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि भारत 2020 में चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण करेगा। पृष्ठ 12

आईआईएम संस्थानों की आरक्षण से छूट की मांग

देश के सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम) ने सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण से छूट देने की मांग की है। अभी इन संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने को कहा है। अधिकारियों के मुताबिक आईआईएम संस्थानों का कहना है कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष है और इसमें सभी को बराबर मौका दिया जाता है।

जीएनएफसी को 15 हजार करोड़ रुपये का नोटिस

दूरसंचार विभाग ने सरकारी कंपनी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स ऐंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएनएफसी) को 15 हजार करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा है। कंपनी ने बुधवार को बीएसई को बताया कि के पास 2005-06 से 2018-19 तक वी-सैट और आईएसपी लाइसेंस थे जिसके एवज में उस पर करीब 15019.97 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें ब्याज भी शामिल है। दूरसंचार विभाग ने उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर के फैसले के बाद यह नोटिस भेजा है।

साल के पहले दिन सेंसेक्स और निफ्टी में हल्की बढ़त

बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स नए साल 2020 के पहले दिन बुधवार को 52.28 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। वित्त, आईटी, एफएमसीजी और बिजली कंपनियों के शेयरों में लाभ से सेंसेक्स में मजबूती का रुख रहा। सेंसेक्स 0.13 फीसदी की बढ़त के साथ 41,306.02 अंक पर बंद हुआ। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14.05 अंक या 0.12 फीसदी की बढ़त के साथ 12,182.50 अंक पर बंद हुआ।

रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क घटा

सरकार ने बुधवार को रिफाइंड पामोलिन पर आयात शुल्क 50 फीसदी से घटाकर 45 फीसदी कर दिया है। इसी तरह, कच्चे पाम तेल पर भी शुल्क 40 फीसदी से कम होकर 37.5 फीसदी रह गया है। यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये दोनों उद्योग आयात शुल्क में कटौती का यह कहते हुए विरोध कर रहे थे कि इससे घरेलू रिफाइनरों को नुकसान होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आसियान समझौते और इंडिया-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता के तहत यह कटौती गई है। पृष्ठ 6

नई परियोजनाओं में तेजी दर्ज

दिसंबर तिमाही में देश में क्षमता उपयोगिता में कमी के बावजूद परियोजनाओं में तेजी

सचिन मामबटा और अमृता पिल्लै
मुंबई, 1 जनवरी

दिसंबर 2019 को समाप्त हुई तीन महीने की अवधि में नई परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले यह रकम अधिक है। दिसंबर 2018 में नई परियोजनाओं में 3.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक रकम आई थी। परियोजनाओं पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार सालाना आधार पर यह रकम 37.4 प्रतिशत बढ़कर 4.26 लाख करोड़ रुपये हो गई।

सीएमआईई प्रत्येक तिमाही के अंत में पूंजीगत व्यय के आंकड़े जारी करता है। सीएमआईई के अनुसार रुकीं परियोजनाओं का अनुपात 81.8 प्रतिशत कम होकर 0.58 लाख करोड़ रुपये रह गया है। पूरी हो चुकीं परियोजनाओं का अनुपात भी इसी स्तर पर है। दिसंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार यह आंकड़ा 1.37 लाख करोड़ रुपये रहा और दिसंबर 2019 में यह बढ़कर 1.36 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

दिलचस्प बात है कि क्षमता के इस्तेमाल में कमी के बावजूद नई परियोजनाओं में तेजी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 दिसंबर को मौद्रिक नीति समिति बैठक में जारी अपनी टिप्पणी में कहा था कि सितंबर तिमाही में क्षमता उपयोगिता 68.9 प्रतिशत थी। इससे पहले यह 73.6 प्रतिशत रही थी। समयानुसार समायोजित आधार पर ऐसी ही गिरावट देखी गई है।

आरबीआई ने कहा, 'समयानुसार समायोजित क्षमता उपयोगिता भी समान अवधि में 74.6 प्रतिशत से कम होकर 69.8 प्रतिशत रह गई। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। इससे क्षमता विस्तार के लिए निवेश में उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। इसका असर पूंजीगत वस्तुओं पर हुआ है।

सुधार के दिख रहे आसार!
(आंकड़े लाख करोड़ रुपये में)

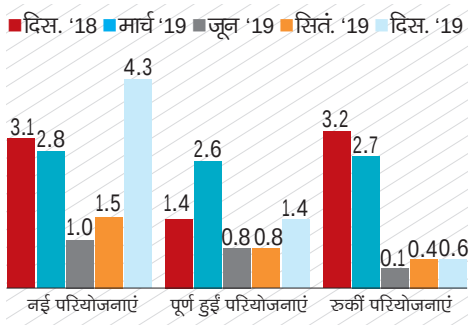

दिसंबर 2018 के आंकड़े पूर्व में प्राप्त आंकड़ों पर आधारित हैं।
स्रोतः सीएमआईई

ब्रोकरेज कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेस के अनसुार एबीबी इंडिया और सीमेंस इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों को मांग में कमी से रूबरू होना पड़ रहा है। हाल के तिमाही आंकड़ों में एबीबी को मिलने वाले नए कारोबार की वृद्धि दर कम होकर 14 प्रतिशत रह गई। विश्लेषक नीलेश भैया और प्रतीक सिंह की 6 दिसंबर को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन, खाद्य एवं बेवरिजेज जैसे बाजारों में सुस्ती इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है।

सरकार ने अपनी तरफ से निवेश बढ़ाने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 1.02 लाख करोड़ रुपये की ढांचागत निवेश योजना का खुलासा किया है। इनमें कुछ हिस्सों पर काम चल भी रहा है।

31 दिसंबर को जारी नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर गठित कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में ढांचागत परियोजनाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है,' बड़ी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए धन की कमी सबसे बड़ी चुनौतर है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की पेचीदा प्रक्रिया और मुआवजे का भुगतान, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, परियोजाओं में देरी से लागत में इजाफा आदि चुनौतियां भी ढांचागत क्षेत्र की रफ्तार कम कर रही हैं।'

रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के जरिये कुछ मुद्दे दूर करने की बात कही गई है। इनमें परियोजनाओं के लिए रकम मुहैया करने के लिए बॉन्ड एवं साख बाजार को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा बेहतर निगरानी ढांचा और पर्यावरण आदि से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर एवं लीडर-इन्फ्रास्ट्रक्चर, मनीष अग्रवाल ने कहा कि हालिया योजना की समय अवधि पर सबकी नजरें होंगी।

जीएसटी फिर 1 लाख करोड़ पार

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 1 जनवरी

दिसंबर में लगातार दूसरे महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से धिक रहा। हालांकि चालू वित्त वर्ष के आखिरी चार महीने के लिए तय लक्ष्य 1.10 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले संग्रह कम रहा। हालांकि दिसंबर के आंकड़े राजस्व संग्रह में स्थिरता का संकेत जरूर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कर प्रवंचना रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण जीएसटी संग्रह में सुधार दिख रहा है।

दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.031 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो नवंबर में दर्ज 1.034 करोड़ रुपये से थोड़ा कम रहा। नवंबर में दर्ज जीएसटी संग्रह सात महीनों का सर्वश्रेष्ठ स्तर था। बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसमें सालाना आधार पर 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। जीएसटी के ये आंकड़े नवंबर के हैं, जिनका संग्रह दिसंबर में हुआ है। दिसंबर का आंकड़ा सरकार के लिए राहत पहुंचाने वाला है, जो इस समय राजस्व की तंगी से जूझ रही है। राजस्व सचिव ने दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच 1.10 लाख करोड़ रुपये राजस्व संग्रह पर जोर दिया है। इनमें कम से कम एक महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा अर्जित करने का लक्ष्य तय किया गया है। घरेलू लेनदेन पर जीएसटी संग्रह में 16 प्रतिशत वृद्धि देखी गई, जो इस वित्त वर्ष सर्वाधिक रहा है। आयात पर जीएसटी संग्रह दर लगातार नकारात्मक (-10 प्रतिशत)रही, जो नवंबर में (-13 प्रतिशत) दर्ज हुई थी। यह घरेलू स्तर पर मांग और उत्पादन में कमजोरी बने रहने का संकेत दे रहा है।

ईवाई में पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कर प्रवंचना रोकने के सरकारी उपायों के कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। राजस्व चोरी रोकने के लिए जीएसटी परिषद ने दिसंबर में कुछ उपायों की घोषणा की थी। परिषद में कहा गया था कि जो कारोबारी संबंधित इनवॉयस अपलोड नहीं करेंगे, उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की कुल रकम का मात्र 10 प्रतिशत तक का ही भुगतान किया जाएगा। दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 19,962 करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर में 19,592 करोड़ रुपये था। राज्य जीएसटी संग्रह 26,762 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले महीने के 27,144 करोड़ रुपये से कम रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 48,099 करोड़ रुपये से कम रहा। नवंबर में यह आंकड़ा 49,028 लाख करोड़ रुपये रहा था।

स्थिरता के संकेत

- दिसंबर में जीएसटी संग्रह रहा 1.03 लाख करोड़ रुपये
- जीएसटी चालू वित्त वर्ष के आखिरी चार महीने के लिए तय 1.10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से रहे कम
- दिसंबर के आंकड़े सरकार के लिए राहत देने वाले

बीएस बातचीत

'अवधि ऋण में हमारा प्रदर्शन अच्छा है'

अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ने, क्रेडिट वृद्धि के सपाट रहने और आरबीआई की एनपीए बढ़ने की चेतावनी के बीच भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन **रजनीश कुमार** ने **सुब्रत पांडा**, **अभिजित लेले** और **देव चटर्जी** से बातचीत में कहा कि अर्थव्यवस्था का बुरा दौर बीत चुका है और पूंजीगत खर्च के चक्र को बहाल करने की जरूरत है। पेश हैं संपादित अंशः

आप देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह देखते हैं?

मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर से बाहर आ चुकी है और अब इसमें सुधार आना चाहिए। वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही अच्छी रही है। दुनिया में उथलपुथल चल रही है और सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इससे जूझ रही हैं। इससे हमारा निर्यात भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर निजी क्षेत्र में पूंजीगत खर्च के चक्र की बहाली सबसे अहम चीज है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ ऐसा हो सकता है।

कॉरपोरेट उधारी में आपका प्रदर्शन कैसा है?

कार्यशील पूंजी का उपयोग अभी सुस्त है और मार्च से कम है। दूसरी ओर हमने सावधि ऋण की श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन किया है। दिसंबर तक एसबीआई के सावधि ऋणों में पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी की बढ़त हुई है और यह 1.72 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल हमारे लिए असाधारण परिस्थिति थी क्योंकि हमने दूसरी छमाही में व्यापक पैमाने पर कर्ज का वितरण किया था। इस वर्ष वैसी ही स्थिति है जैसी पहले होती थी। घरेलू बाजार में हमारी उधारी पिछले साल की तुलना में 40,000 करोड़ रुपये कम है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है।

7 जून के परिपत्र के तहत इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट (आईसीए) ढांचे के बारे में आपका क्या कहना है?

कुल 34 खातों में आईसीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर हम दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) को छोड़ दें तो हमें उम्मीद है कि जनवरी-मार्च तिमाही में हमें परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर कोई चौंकाने वाली बात देखने को मिलेगी। इन 34 खातों में से 21 खाते पहले से ही गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) हैं और फंसे कर्ज का एक बड़ा हिस्सा हैं। इन खातों में एसबीआई का 57,000 करोड़ रुपये और पूरे बैंकिंग क्षेत्र का करीब 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश है।

क्या आईसीए काम कर रहा है?

इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है कि छह-सात महीने में किसी कंपनी का समाधान निकालना मुश्किल है। इसलिए आईसीए को सही ढंग से काम करने के लिए कम से कम नौ-दस महीने का समय दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर निर्धारित समय में समाधान नहीं होता है तो हम सभी कंपनियों को एनसीएलटी में नहीं भेज सकते हैं। अब बैंक इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अगर किसी कंपनी को एनसीएलटी में भेजा जाता है तो उसकी कितनी वसूली होगी। ■ शेष पृष्ठ 3

'सुस्ती' से उबरीं मारुति-महिंद्रा

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और निसान ने दिसंबर महीने में घरेलू बिक्री में बढ़त दर्ज की। हुंडई, होंडा और टोयोटा की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। मारुति सुजूकी ने कहा कि दिसंबर में घरेलू बाजार में उसकी बिक्री 2.4 प्रतिशत बढ़कर 1,24,375 वाहन रही, जो एक साल पहले इसी महीने में 121,479 थी। कंपनी ने कहा कि नई वैगनआर, स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, समेत कॉम्पैक्ट श्रेणी की बिक्री 27.9 प्रतिशत बढ़कर 65,673 वाहन पर पहुंच गई। एक साल पहले इसी महीने उसने 51,346 वाहनों की बिक्री की थी। *एजेंसी*

त्यापार गोष्ठी

नए साल से आर्थिक एवं कारोबारी उम्मीदें ?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या नई परियोजनाओं में तेजी है अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या ढांचागत क्षेत्र पर जोर देने से देश की अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी
हां **80.00%**
नहीं **20.00%**

रिकॉर्डतोड़ ठंड से रूम हीटर की बिक्री को दम

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 1 जनवरी

- भारी मांग से बाजार में होने लगी हीटर की किल्लत, पुराना स्टॉक खत्म
- हीटर खरीदने के लिए ग्राहकों को करना पड़ रहा है इंतजार

दिल्ली में जबरदस्त ठंड से रूम हीटरों की बिक्री में खासी तेजी आई है। हालत यह है कि कारोबारी इनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मांग में तेजी के बाद अब खुदरा कारोबारियों ने भी रूम हीटरों के दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले कुछ सालों से जमा हीटरों से परेशान रहने वाले कारोबारियों का पुराना माल ठंड खत्म होने से पहले ही निकल चुका है। दिल्ली स्थित भागीरथ प्लेस बाजार हीटर, गीजर समेत अन्य इलेक्ट्रिकल सामानों के कारोबार का प्रमुख केंद्र है। भागीरथ प्लेस में ही रूम हीटर, हीजर, पानी गर्म करने की रॉड का कारोबार करने वाले एक कारोबारी ने बताया, 'पिछले साल उन्होंने 6 से 8 लाख रुपये की बिक्री ही की थी, इस साल अब तक 12 लाख रुपये की बिक्री हो चुकी है।'

मयूर बिहार फेज-3 के खुदरा इलेक्ट्रिकल कारोबारी सोनू गुप्ता ने कहा कि ब्रांड एवं लोकल रूम हीटर का स्टॉक खत्म हो चुका है और ग्राहकों की मांग पूरी करने करने में अब उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। गुप्ता ने कहा कि पिछले साल 600 से 800 रुपये में बिकने वाले रूम हीटर इन दिनों 750 से 1,000 रुपये में बिक रहे हैं। रूम हीटर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक में मिल रहा है।

एनआरटीटी के ब्योरे पर आईटी की नजर

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 1 जनवरी

जांच का घेरा

- 2015 में किया था एफआरसीए पंजीकरण के लिए आवेदन
- परोपकारी संस्था का दर्जा वापस करने का किया था अनुरोध

आय कर विभाग नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट (एनआरटीटी) विदेशी चंदा स्वीकार करने के लिए दिसंबर 2015 में किए गए आवेदन की जांच कर रहा है। ट्रस्ट ने उसी वर्ष परोपकारी संस्था के अपने दर्जे को वापस करने की पेशकश की थी। एनआरटीटी टाटा ट्रस्ट्स के उन छह ट्रस्टों में शामिल है जिनका पंजीकरण आय कर विभाग ने पिछले साल अक्टूबर में रद्द किया था।

एनआरटीटी ने विदेशी चंदा स्वीकार करने के लिए विदेशी चंदा नियमन कानून (एफआरसीए) की धारा 11 (1) के तहत 10 दिसंबर, 2015 को एक आवेदन दिया था। ट्रस्ट का दावा था कि उसका एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है। उसने फरवरी, 2015 में परोपकारी संस्था का दर्जा छोड़ने के बाद यह आवेदन किया था।

एफसीआरए आवेदन में ट्रस्ट ने विस्तार से अपनी गतिविधियों के बारे में बताया था। ट्रस्ट ने दावा किया था कि उसका गठन 1974 में रतन नवल टाटा ने अपनी दादी लेडी नवाजबाई रतन टाटा की याद में किया था। उसने साथ ही कहा कि ट्रस्ट मुंबई में चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय में पंजीकृत है।

उनका पंजीकरण आय कर कानून, 1961 की धारा 12ए के तहत किया गया है। इस धारा के तहत कुछ खास तरह की संस्थाओं को आय कर में छूट का प्रावधान है। जब किसी संस्था को धारा 12ए के तहत ट्रस्ट या गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत किया जाता है तो वे आय कर में पूरी छूट की हकदार होती हैं। अपने वित्तीय लेनदेन से मुनाफा नहीं कमाने वाले ट्रस्ट और स्वयंसेवी संगठन 12ए के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। अगर कोई गैर-लाभकारी ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्था 12ए के तहत पंजीकृत नहीं है तो उसकी वित्तीय प्राप्तियों या लेनदेन को कर योग्य माना जाता है।

अपनी गतिविधियों के अलावा एनआरटीटी ट्रस्ट डीड और तीन वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2013, 2014 और 2015) के अंकेक्षित बहीखाते भी सौंपे थे। इस बारे में बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा भेजे गए ईमेल के जवाब में टाटा ट्रस्ट्स के प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि ट्रस्ट आय कर कानून की धारा 12ए के तहत पंजीकृत है, इसलिए उन वित्त वर्षों के लिए जानकारी से इसका जिक्र किया गया था। ट्रस्ट ने फरवरी 2015 में 12ए के तहत पंजीकरण को वापस कर दिया था लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया। यह अनजाने में हुई चूक थी।

एनआरटीटी ने दिसंबर 2015 में एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदन दिया था। आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ट्रस्ट को पिछले तीन वित्त वर्षों यानी 2012-13, 2013-14 और 2014-15 की गतिविधियों की जानकारी देनी थी। टाटा ट्रस्ट्स का कहना है कि जहां तक एफसीआर आवेदन का सवाल है तो इसका 12ए के तहत पंजीकरण से कोई लेनादेना नहीं है। इस आवेदन से जुड़े नियमों के तहत किसी ट्रस्ट का आय कर कानून की धारा 12ए के तहत पंजीकरण जरूरी नहीं है।

खबरों में रहे स्टॉक

टाइटन कंपनी

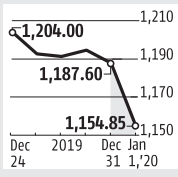

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज्यादा टूटने वाला

₹ 1,187.60 पिछला बंद भाव
₹ 1,154.85 आज का बंद भाव
▼ 2.76 %

अदाणी ग्रीन एनर्जी

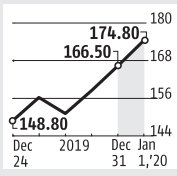

75 मेगावॉट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू

₹ 166.50 पिछला बंद भाव
₹ 174.80 आज का बंद भाव
▲ 4.98 %

लार्सन ऐंड टुब्रो

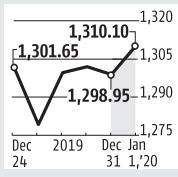

बुनियादी ढांचा पर 102 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की सरकारी योजना

₹ 1,298.95 पिछला बंद भाव
₹ 1,310.10 आज का बंद भाव
▲ 1.00 %

एस्कॉर्ट्स

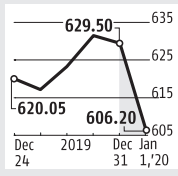

दिसंबर में ट्रैक्टर की बिक्री सालाना आधार पर 10 फीसदी घटी

₹ 629.50 पिछला बंद भाव
₹ 606.20 आज का बंद भाव
▼ 3.70 %

डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज

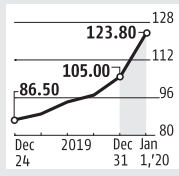

सकारात्मक परिदृश्य पर चीनी शेयरों में तेजी, एक हफ्ते में 47 फीसदी उछली

₹ 105.00 पिछला बंद भाव
₹ 123.80 आज का बंद भाव
▲ 17.91 %

संक्षेप में

रूट मोबाइल के आईपीओ को सेबी की हरी झंडी

रूट मोबाइल को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए अनुमानित तौर पर 600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। इस आईपीओ में 350 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे जबकि प्रवर्तक संदीप कुमार गुप्ता और राजदीप कुमार गुप्ता 65 लाख शेयरों की बिक्री ओएफएस के जरिए करेंगे। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आईडीबीआई कैपिटल और येस सिक्योरिटीज इस इश्यू के बैंकर हैं। *बीएस*

बबीता रायडू सेबी की नई कार्यकारी निदेशक

बबीता रायडू ने बुधवार को बाजार नियामक सेबी की नई कार्यकारी निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। रायडू कानूनी मामलों के विभाग, प्रवर्तन विभाग और विशेष प्रवर्तन प्रकोष्ठ का कामकाज देखेंगी। कार्यकारी निदेशक बनाए जाने से पहले रायडू सेबी के कानूनी मामलों के विभाग में कार्यरत थीं। *बीएस*

समीर वॉलमार्ट इंडिया उप-मुख्य कार्याधिकारी बने

रिटेल कंपनी वॉलमार्ट इंडिया ने अपने मुख्य कारोबारी अधिकारी समीर अग्रवाल को उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उप-सीईओ) के पद पर पदोन्नत किया है। *भाषा*

सस्ता होगा टीवी का मासिक बिल!

सोहिनी दास
मुंबई, 1 जनवरी

उपभोक्ताओं को राहत देने की कवायद

- ट्राई ने नए टैरिफ ऑर्डर नियमों में किया संशोधन
- प्रसारकों को 15 जनवरी तक जारी करनी होंगी नई कीमतें
- एनसीएफ में नहीं जोड़े जाएंगे सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए चैनल
- डीटीएच या केबल के लिए 100 चैनलों के लिए एनएफसी शुल्क 153 रुपये (कर सहित) निर्धारित

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नए टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ) में संशोधन जारी किए हैं जो बढ़े हुए मासिक बिल पर उपभोक्ताओं की चिंता दूर करने का प्रयास करता है। नियामक ने मूल्य निर्धारण पर जारी दिशानिर्देश के बाद प्रसारकों से 15 जनवरी तक अपने चैनल की नई कीमतें जारी करने के लिए कहा है।

एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्राई ने 200 चैनलों के साथ अधिकतम नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) को 130 रुपये (कर अतिरिक्त) कर दिया है। डीटीएच या केबल टेलीविजन कनेक्शन के लिए अब 100 चैनलों के लिए एनएफसी शुल्क 153 रुपये (कर सहित) निर्धारित किया गया है।

ट्राई का कहना है कि उन्होंने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और इसके हिसाब से नए नियामक ढांचे के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया। फरवरी 2019 से लागू हुए एनटीओ के अनुसार, उपभोक्ता अपने हिसाब से टीवी चैनलों का चयन कर सकते हैं और ग्राहकों को केवल उन्हीं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) देना होगा। इससे पहले, उपभोक्ताओं को पहले से तैयार किए गए चैनलों के समूह में से ही चयन करना होता था। एनटीओ से ग्राहकों के मासिक बिल में कमी आने की उम्मीद थी लेकिन परिणाम इसके विपरीत आए। नियामक ने एनटीओ को लेकर दो परामर्श पत्र जारी किए, पहला अगस्त में और दूसरा सितंबर माह में।

केवल चुने गए चैनलों का शुल्क देने के मुकाबले प्रसारकों द्वारा चीवी चैनल समूह बनाने के साथ भारी छूट देने की समस्या को देखते हुए बुधवार को प्राधिकरण ने दो सुझाव दिए हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल चुने गए चैनलों का कुल शुल्क बहुत अधिक न हो जाए। पहला, भुगतान किए जाने वाले सभी चैनलों को मिलाकर एक समूह बनाया जा सकता है और उसे पैकेज के तौर पर पेश किया जा सकता है। दूसरा, भुगतान करके खरीदे जाने वाले प्रत्येक चैनल को मिलाकर बनाए गए समूह की कुल कीमत सर्वाधिक महंगे चैनल की कीमत के तीन गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ट्राई ने निर्णय लिया है कि केवल 12 रुपये या इससे कम कीमत वाले चैनलों को ही इस तरह के समूह में शामिल किया जा सकता है।

उद्योग से जुड़े सूत्रों का मानना है कि यह एनटीओ के नियमों में बड़ा बदलाव है और अब प्रसारकों को अपने प्लान की कीमतें सावधानीपूर्वक निर्धारित करनी होंगी।

नियामक ने 130 रुपये (कर अतिरिक्त) के अधिकतम एनएफसी में 200 चैनलों का प्रावधान किया है। ट्राई का कहना है, 'यह भी निर्णय लिया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनिवार्य किए गए चैनलों को एनसीएफ में शामिल चैनलों के साथ नहीं गिना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म नेटवर्क (डीपीओ) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर चैनल उपलब्ध कराने के लिए 160 रुपये महीना से अधिक शुल्क नहीं ले सकते।'

छोटे, मझोले कारोबारियों ने घटाया साइबर सुरक्षा बजट

भले ही साल 2019 में साइबर सुरक्षा पर खर्च सालाना आधार पर करीब नौ प्रतिशत तक बढ़ा हो लेकिन छोटे तथा मझोले कारोबार एवं उद्योगों के लिए यह औसत खर्च से कम रहा है। एक आईटी रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर साल 2019 में छोटे तथा मझोले उद्यमों का आईटी सुरक्षा पर औसत खर्च 2.05 लाख डॉलर तथा बड़े कारोबारियों के लिए 80 लाख डॉलर रहा और इनमें से 45 प्रतिशत छोटे तथा मझोले उद्यम एवं 50 प्रतिशत कारोबारियों ने औसत खर्च से कम राशि खर्च की है।

यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाली साइबर सुरक्षा कंपनी कैसपर्सकी में बी2बी प्रोडक्ट मार्केटिंग के प्रमुख सर्गेई मार्तस्यन्क्यान ने कहा, 'बजट की योजना तैयार करना कंपनियों के लिए अहम होता है क्योंकि उचित निवेश यह सुनिश्चित करता है कि क्या एक कंपनी वर्तमान साइबर सुरक्षा चुनौतियों और खतरों को पूरा करने के लिए तैयार है। हालांकि यह जटिल कार्य हो सकता है क्योंकि इसके लिए साइबर सुरक्षा तथा कारोबार की बेहतर समझ होना जरूरी है, जिससे इसकी आवश्यकता तथा लागत को संतुलित किया जा सके।'

छोटे तथा मझोले कारोबारियों के लिए बजट तैयार करना और जटिल हो जाता है क्योंकि यह केवल पैसों की बात नहीं है बल्कि बजट के लिए बनाई जाने वाली योजना प्रक्रिया का एक अहम कारक है। रिपोर्ट बताती है कि ऐसा करना व्यावसायिक सेवाओं के लिए प्रासंगिक साइबर सुरक्षा जोखिमों एवं सुरक्षा विधियों में मानव संसाधन तथा विशेषज्ञता की मांग के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अमेरिकी कंपनी के मुताबिक उद्यमी आंतरिक स्तर पर सुरक्षा परिचालन केंद्र स्थापित करके डेटा चोरी के वित्तीय प्रभाव को कम कर सकते हैं। एसओसी तात्कालिक सुरक्षा घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। *बीएस*

बीएस बातचीत

हम भारतीय बाजार पर सकारात्मक बने हुए हैं

वर्ष 2019 में मांग पर दबाव के बावजूद निर्माण उपकरण निर्माता जेसीबी इंडिया ने 650 करोड़ रुपये की नई इकाई पर काम करने का निर्णय लिया है। अगस्त 2019 में जेसीबी इंडिया के एमडी एवं सीईओ की जिम्मेदारी संभालने वाले **सुबीर कुमार चौधरी** ने **टीई नरसिम्हन** को बताया कि भारतीय बाजार का दीर्घावधि परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है। बातचीत के मुख्य अंश:

आप मंदी का किस तरह से मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं?

जेसीबी ने भारत में नवाचार-केंद्रित परिचालन के चार दशक पूरे किए हैं। पिछले 14-15 वर्षों में हमने कई मंदी के चक्र महसूस किया, लेकिन हर बार बाजार ने मजबूती के साथ वापसी की। हम स्वदेशीकरण, निर्माण, कौशल एवं नवाचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करेंगे। हम स्वयं को ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिए तैयार करेंगे जो वैल्यू, नई डिजिटल प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठ गुणवत्ता के समावेश की पेशकश करते हैं।

क्या इससे जेसीबी की निवेश योजनाएं प्रभावित होंगी?

गुजरात में 650 करोड़ रुपये की नई इकाई अगले साल तक तैयार हो जाएगी और यह वैश्विक उत्पादन इकाइयों के लिए कलपुर्जे तैयार करेगी। यह सालाना 85,000 टन इस्पात का संवर्द्धन कर सकेगी और भारत में जेसीबी की 5वीं फैक्टरी होगी। नई इकाई दुनियाभर में मौजूद जेसीबी की फैक्टरियों के लिए कलपुर्जे बनाएगी। यह निर्यात-केंद्रित इकाई होगी। भारत में निर्मित उत्पादों का मौजूदा समय में 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाता है।

अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में मंदी का जेसीबी के परिचालन पर कितना असर पड़ रहा है?

पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों और राजमार्गों के विकास पर जोर दिए जाने की वजह से वर्ष 2018 इस उद्योग और जेसीबी इंडिया के लिए शानदार वर्ष था। इससे इस बात का संकेत मिला कि निर्माण उपकरण उद्योग में आने वाले वर्षों में हमें किस तरह अवसर मिल सकते हैं। 2018 की तुलना में, 2019 में मांग पर दबाव देखा गया। 2017 की तुलना में उपकरण बिक्री के संदर्भ में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2018 जेसीबी इंडिया के लिए मजबूत वर्ष था। वहीं 2019 में कुछ गिरावट देखी गई। लेकिन हमारा मानना है कि इस साल के मध्य तक हालात में सुधार आएगा। मंदी और बाजार की जरूरत को देखते हुए हमने अपने व्यवसाय में बदलाव किया है। हालांकि भारतीय बाजार के संदर्भ में हमारा दीर्घावधि नजरिया सकारात्मक बना हुआ है। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचा विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता से निकट भविष्य में वृद्धि के अवसर मौजूद होंगे। बुनियादी ढांचा गतिविधियों में मंदी आई है जिससे हमारा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। हालांकि भारत के वर्ष 2024 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील होने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास जरूरी है और हमें उम्मीद है कि हालात में सुधार आएगा। हम सकारात्मक बदलाव के कुछ संकेत देख रहे हैं। बुनियादी ढांचा विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निवेश को देखते हुए हमें इस उद्योग में संभावनाएं बरकरार रहने का अनुमान है।

क्या नकदी संकट या आईएलऐंडएफएस ऋण संकट का बाजार पर गंभीर असर देखा गया है?

नकदी चक्र के साथ साथ एनबीएफसी क्षेत्र में दबाव देखा गया है जिससे हमारे लिए मंदी गहरा रही है। आईएलऐंडएफएस इस सेगमेंट में प्रमुख है। इससे यह स्वाभाविक है कि क्षेत्र की संपूर्ण धारणा पर इसका प्रभाव पड़ेगा। व्यापक प्रभाव और नकदी की किल्लत की वजह से बाजार में दबाव देखा गया है। सरकार आर्थिक वृद्धि में सुधार लाने, नकदी समस्याएं सुलझाने और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक धारणा फिर से लौटाने के लिए कई जरूरी कदम उठा रही है। हमारा मानना है कि अब हालात में सुधार आएगा। ठोस प्रयासों के साथ आगामी वर्षों में निर्माण उपकरण उद्योग के लिए परिदृश्य सकारात्मक दिख रहा है।

एपीजे सुरेंद्र पार्क्स लाएगी आईपीओ

एपीजे सुरेंद्र पार्क्स होटल्स ने बुधवार को 1,000 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के लिए पेशकश दस्तावेज का मसौदा जमा करा दिया। इस कंपनी के पास मशहूर बेकरी ब्रांड फ्लरीज का स्वामित्व है। कंपनी ने पेशकश दस्तावेज का मसौदा बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराया है। आईपीओ में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे जबकि 600 करोड़ रुपये का ओएफएस होगा। कंपनी इस आईपीओ में नए शेयर जारी करने से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल उधार चुकाने में करेगी।

एपीजे सुरेंद्र पार्क्स होटल्स के पास भारत में द पार्क्स ब्रांड के तहत लक्जरी बुटिक होटल्स का स्वामित्व है। अभी भारत के 15 शहरों में कंपनी 1,937 कमरे के साथ 22 होटल का परिचालन करती है और कंपनी के पास उसका स्वामित्व भी है। कंपनी का खुदरा फूड व बेवरिज कारोबार फ्लरीज ब्रांड के तहत है। *बीएस*

2019 में मारुति ने बेचीं नौ साल में सबसे कम कार

कमजोर आर्थिक वृद्धि व खपत घटने से बिक्री पर दबाव

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 1 जनवरी

कार निर्माता मारुति सुजूकी इंडिया की बिक्री में कैलेंडर वर्ष 2019 में सालाना आधार पर 12.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। बिक्री में गिरावट लगभग एक दशक में सबसे ज्यादा रही। कमजोर आर्थिक वृद्धि और खपत घटने से कंपनी की बिक्री पर दबाव पड़ा। भारत की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में 4.5 फीसदी की कमजोर दर से बढ़ी, जो 5 साल में सबसे कम थी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए वर्ष से मारुति को उम्मीद है, लेकिन वह बीएस-6 के क्रियान्वयन से पहले अगले कुछ महीनों में अनिश्चितताओं को लेकर सतर्क बनी हुई है।

ब्लूमबर्ग के आंकड़े के अनुसार वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में बलेनो और ब्रेजा मॉडलों की बिक्री एक साल पहले के 18 लाख वाहनों से घटकर 16 लाख रह गई। 12 वर्ष में यह दूसरी बार है जब जापानी कार निर्माता की स्थानीय कंपनी ने अपनी बिक्री में गिरावट दर्ज की है। मारुति की बिक्री कैलेंडर वर्ष 2011 में पूर्ववर्ती वर्ष के 12 लाख वाहनों की तुलना में 8.1 प्रतिशत घटकर 11 लाख वाहन रह गई।

मारुति सुजूकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, 'पिछला वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण था। भविष्य में सतर्क रहने और आशान्वित होने की वजह दिख रही हैं।' उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा कर्ज की दरों में कमी और ग्रामीण बिक्री में सुधार सकारात्मक हैं।

हालांकि वह इसे लकर सतर्क बने हुए हैं कि स्वामित्व की लागत चालू वर्ष में ऊंचे स्तरों पर बने रहने की आशंका है। इससे दबाव पैदा हो सकता है। बीएस-6 से बिक्री में मजबूती आएगी। ब्रेजा और एस क्रॉस के पेट्रोल बीएस-6 वैरिएंट्स की पेशकश से भी मारुति की कुल बिक्री में मदद मिलेगी।

इस बीच, मारुति अप्रैल से डीजल कारों का उत्पादन बंद किए जाने के बाद पैदा हुई कमी की भरपाई के लिए सीएनजी मॉडलों पर दांव लगा रही है। कंपनी का मानना है कि यदि सरकार ऐसे वाहनों पर जीएसटी घटाती है तो सीएनजी मॉडलों की बिक्री में इजाफा हो सकता है।

श्रीवास्तव का कहना है कि कुछ नीतिगत बदलावों, स्वामित्व की लागत में वृद्धि, पथ कर में वृद्धि, नकदी संकट वाहनों पर जीएसटी दर में संभावित कमी की चर्चा ने खरीदारों को खरीदारी टालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर दबाव से भी चिंताओं में इजाफा हुआ।

रिलायंस सिक्योरिटीज में विश्लेषक मितुल शाह ने कहा, 'इन सभी विपरीत कारकों ने 2019 में उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाला। जब तक बीएस-6 का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो जाता, तब तक कुछ महीनों तक यह दबाव बना रहेगा।' शाह का मानना है कि यात्री वाहन खंड में वित्त वर्ष 2021 से ही मजबूत वृद्धि दिखेगी। उन्हें मारुति की नई वाहन पेशकशों से भी बिक्री में सुधार आने की उम्मीद है।

मारुति सुजूकी को नए साल से उम्मीद

- कंपनी ने कहा, पिछला वर्ष बेहद चुनौतीपूर्ण था। भविष्य में सतर्क रहने और आशान्वित होने की वजह दिख रही हैं
- कंपनी का मानना है कि बैंकों द्वारा कर्ज की दरों में कमी और ग्रामीण बिक्री में सुधार सकारात्मक हैं

हीरो इलेक्ट्रिक ने 700 करोड़ रुपये का निवेश टाला

देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी 700 करोड़ रुपये की निवेश योजना को एक साल के लिए टाल दिया है।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि फेम-दो योजना वांछित नतीजे देने में विफल रही है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र नीचे आ रहा है। इस वजह से कंपनी को अपनी निवेश योजना को टालना पड़ा।

हीरो इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक नवीन मुंजाल ने कहा, कंपनी चाहती है कि इस नीति को पुनर्गठित किया जाए। कंपनी चाहती है कि कम रफ्तार के दोपहिया को भी सब्सिडी के लिए शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये लागत दक्ष वाहन महत्वपूर्ण हैं। मुंजाल ने कहा, 'उद्योग के दृष्टिकोण से फेम-एक में कुछ हो रहा था लेकिन फेम-दो के आने के बाद, चाहे कोई भी तर्क या वजह हो, जिस तरीके से फेम-दो लागू किया गया, उससे पूरा उद्योग नीचे आ गया। हालांकि अब उद्योग उससे उबर रहा है।'

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के संगठन एसएमईवी के फेम-दो के पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री अप्रैल-दिसंबर, 2019 की अवधि में मात्र 3,000 इकाई रही है। *भाषा*

सावधि ऋण में एसबीआई का प्रदर्शन बेहतर

पृष्ठ-1 का शेष

क्या आपको लगता है कि आईबीसी सफल रहा है?

एस्सार स्टील के फैसले के बाद मैं आईबीसी को लेकर बेहद संतुष्ट हूं। विदेशी निवेशक भी वापस आएंगे। हमने देखा है कि एस्सार स्टील में आर्सेलर मित्तल की तरफ से 42,000 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है। यह अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए सकारात्मक खबर है क्योंकि कंपनी में और निवेश आएगा। रतन इंडिया के मामले में भी विदेशी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। कई कंपनियों का समाधान हो रहा है। दिसंबर में ही चार कंपनियों एस्सार स्टील, रुचि सोया, प्रयागराज पावर और रतन इंडिया का समाधान हुआ है। जेपी इन्फ्राटेक का मामला भी मार्च तक सुलझने की संभावना है। इसके अलावा भूषण पावर ऐंड स्टील, आलोक इंडस्ट्रीज और रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी समाधान हो सकता है। आईबीसी के तहत रिकॉर्ड संख्या में मामले दायर किए गए हैं।

क्या एनबीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता की चिंता दूर हो गई हैं?

मुझे लगता है कि यह सही है। मुझे तत्काल किसी चूक या खतरे का अंदेशा नहीं है। यह सही है कि एनबीएफसी का रियल एस्टेट क्षेत्र में अच्छाखासा निवेश है। जो रियल एस्टेट डेवलपर फ्लैटों को रोककर रखे हुए थे, वे अब उन्हें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे सभी जगह रियल एस्टेट की कीमतों में कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई समस्याएं हैं लेकिन बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई में ऐसा नहीं है। इसलिए यह सही है कि बड़ी संख्या में फ्लैट बिके नहीं हैं लेकिन यह समस्या नई नहीं है। अब नई रियल एस्टेट परियोजनाओं की संख्या कम हो गई है और कुछ तैयार फ्लैट भी बिक रहे हैं। इससे मांग और आपूर्ति की समस्या में ठहराव आएगा। इस क्षेत्र पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो पूरी होने के करीब हैं जिनके लिए सरकार ने रियल्टी फंड मुहैया कराया है।

क्या आप मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो से चिंतित हैं?

मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो हमारे लोन बुक का 1.1 फीसदी है। इस तरह अगर इस श्रेणी में 10 फीसदी एनपीए भी होगा तो इससे हम पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। डीएचएफएल जैसे खातों से हम पर असर पड़ेगा क्योंकि अचानक 10,000 करोड़ रुपये का ऋण एनपीए बन जाएगा।

आर्थिक मंदी से प्रभावित होगा राज्यों का राजस्व

अभिजित लेले
मुंबई, 1 जनवरी

चालू वित्त वर्ष 2020 में राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर दबाव रहने की संभावना है। इसकी वजह आर्थिक मंदी, कर राजस्व में कमी और ज्यादा व्यय है। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के मुताबिक ऐसे में उनका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत पर पहुंच सकता है, जो बजट में 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

कुल मिलाकर राज्यों ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 30.97 लाख करोड़ रुपये कुल राजस्व का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 19 का पुनरीक्षित अनुमान (10.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ) 28.10 लाख करोड़ रुपये था।

राज्यों के बजट उनकी विधानसभाओं में पेश किए गए जैसा केंद्र करती है। राज्यों ने वित्तवर्ष 2020 में नॉमिनल जीडीपी में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। लेकिन वित्त वर्ष 202 की पहली छमाही में नॉमिनल वृद्धि दर 7 प्रतिशत थी।

कर राजस्व में वृद्धि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि के समानांतर चलता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि ऐसे में राज्य सरकारों के कर संग्रह में बजट अनुमान की तुलना में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

चालू वित्त वर्ष में कर राजस्व में वृद्धि 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था और इस हिसाब से 22.15 लाख करोड़ रुपये राजस्व आने की संभावना थी। राज्यों का कर संग्रह 3 अलग अलग राजस्वों के हिसाब से घटा है- राज्य का अपना कर राजस्व (एसओटीआर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्रीय कर में हिस्सेदारी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और अनुदान (जीएसटी मुआवजा)।

वित्त वर्ष 2020 में राज्यों का राजकोषीय घाटा हो सकता है जीडीपी का 3 प्रतिशत

वित्त वर्ष 2020 में पिछले साल की तुलना में केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 13.98 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। बहरहाल सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2020 (अप्रैल-अक्टूबर) में सिर्फ 2.7 प्रतिशत बढ़ा है। इसकी वजह से राज्यों के राजकोषीय घाटे को लेकर दबाव बढ़ा है। राज्यों ने केंद्र के कर में से 8.5 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया था। लेकिन केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 में राज्यों का हिस्सा 8.1 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है।

यहां तक कि 8.1 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्त वर्ष 2020 की शेष अवधि में केंद्रीय करों का संग्रह 15.1 प्रतिशत बढ़ाना होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है।

घटा ईरान से कच्चे तेल का आयात

पश्चिम एशिया के अलावा अन्य तेल उत्पादक देशों से आयात बढ़ा रहा भारत

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 1 जनवरी

चालू वित्त वर्ष के दौरान ईरान से कच्चे तेल का आयात घटकर महज 17 लाख टन रह गया है। ईरान ने 2018-19 में 239 लाख टन कच्चा तेल भारत भेजा था और वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। मई के पहले सप्ताह से इस पश्चिम एशियाई देश से भारत ने कच्चे तेल का आयात रोक दिया था।

बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक अगर अमेरिका 2020 की शुरुआत में ईरान से प्रतिबंध हटा नहीं लेता है तो यह पिछले 12 साल में यह ईरान से कच्चे तेल का सबसे कम आयात होगा। ईरान से तेल की कम आवक की भरपाई अमेरिका से आयात के माध्यम से हो रहा है। भारत ने अमेरिका से 2017-18 में 19 लाख टन आयात किया था, जो 2018-19 में बढ़कर 62 लाख टन हो गया। दिलचस्प है कि भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में अमेरिका से 54 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया है, जबकि अमेरिका से आयात अभी हाल में 2017-18 से ही शुरू हुआ है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा, 'यह ऐतिहासिक निचला स्तर है, लेकिन पहले की स्थिति के विपरीत यह भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। हमने अपने बास्केट का विविधीकरण किया है। इससे पश्चिम एशिया पर हमारी निर्भरता कम हुई है। इराक और नाइजीरिया जैसे देशों से भी आयात बढ़ा है।'

इस साल सितंबर तक इराक भारत में सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था और उसने 260 लाख टन आपूर्ति की थी। 207 लाख टन आपूर्ति कर सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहा।

एक सरकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत की कंपनियों ने 4 मई से ईरान से आयात पूरी तरह रोक दिया है और वह ज्यादा विविधीकृत बास्केट पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा, 'ये आंकड़े वित्त वर्ष के पहले 2 महीने पर लागू होंगे।' 2019-20 में भारत के कच्चे तेल बास्केट में हिस्सेदारी वाले अन्य देशों में नाइजीरिया (99 लाख टन), संयुक्त अरब अमीरात (89 लाख टन), कुवैत (57 लाख टन) और मेक्सिको (41 लाख टन) शामिल हैं। अगर मौजूदा 649 लाख टन के आंकड़ों को देखें तो इस साल भारत की पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम हो सकती है।

भारत ने इसके पहले वित्त वर्ष में 2265 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया, जो 2017-18 के 2204 लाख टन की तुलना में 2.7 प्रतिशत ज्यादा है। देश के कच्चे आयात का बिल इस अवधि के दौरान 2017-28 के 87.8 अरब से बढ़कर 111.9 अरब डॉलर हो गया। दिलचस्प है कि इस साल अप्रैल से नवंबर के दौरान कच्चे तेल का कुल आयात 0.7 प्रतिशत घटकर 1499 लाख टन रह गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 1510 लाख टन था। इस अवधि के दौरान आयात बिल 11.7 प्रतिशत कम होकर 69.5 अरब डॉलर हो गया, जो 2018-19 के अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान 78.6 अरब डॉलर था।

इसके बावजूद कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में बढ़कर 84.7 प्रतिशत रही, जो 2018-19 की समान अवधि में 83.3 प्रतिशत थी।

ईरान से आने वाले कच्चे तेल का ज्यादा हिस्सा 2018-19 तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), मंगलूर रिफाइनरी ऐंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और एस्सार ऑयल लिमिटेड (ईओएल) करती थीं। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने 23 दिसंबर को ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ से मुलाकात की थी, लेकिन उसमें बातचीत का अहम मसला चाबहार बंदरगाह था।

भारत में ईरान से कच्चे तेल का आयात

वर्ष	मात्रा लाख टन में
2008-09	213
2009-10	212
2010-11	185
2011-12	181.1
2012-13	134
2013-14	110
2014-15	109.5
2015-16	127
2016-17	272
2017-18	226
2018-19	239
2019-20*	17

*अप्रैल से सितंबर तक
स्रोतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व उद्योग के सूत्र

बीएसएनएल की संपत्ति बेचने के लिए समूह बना

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 1 जनवरी

केंद्र सरकार ने नकदी के संकट से जूझ रही कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की संपत्तियां बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अंतरमंत्रालय समूह का गठन किया गया है। यह समूह कंपनी की रियल एस्टेट को चिह्नित करने व उन्हें बेचने की प्राथमिकता तय करेगा। कंपनी को आर्थिक संकट की वजह से कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत हो रही है और अब तक नवंबर महीने के वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है।

इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस समूह में निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), दूरसंचार और बीएसएलनएल के अधिकारी शामिल होंगे। कंपनी की 40 कीमती जमीनों को चिह्नित किया गया है, जिनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी। इन्हें बेचने से कंपनी को बैलेंस शीट दुरुस्त करने में मदद मिलेगी और 4जी नेटवर्क सेवा शुरू करने के लिए उसे धन मिल सकेगा, जो 2020 की दूसरी छमाही में शुरू होने की संभावना है। अगले 3 साल में कंपनी की संपत्तियों से 37,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

अक्टूबर में केंद्र सरकार ने बीएसएलएल और एमटीएनएल के लिए 69,000 करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी थी। इस पैकेज में घाटे में चल रही दोनों फर्मों का विलय, उनकी संपत्ति बेचकर धन जुटाना और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पैकेज देना, जिससे कि दोनों इकाइयों को अगले 2 साल में मुनाफे में लाया जा सके।

इस बचाव पैकेज में 4जी स्पेक्ट्रम की खरीद के लिए 20,140 करोड़ रुपये, स्पेक्ट्रम आवंटन पर जीएसटी भुगतान के लिए 3,674 करोड़ रुपये, कंपनी द्वारा 15,000 करोड़ रुपये का सॉवरिन गारंटी पर कर्ज लेने और सरकार की ओर से 17,160 करोड़ रुपये का वित्तपोषण शामिल है। सॉवरिन बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया पुनर्गठित कर्ज व अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए होगी। यह बॉन्ड पूरी तरह से पीएसयू का होगा। हाल में घोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के 92,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने स्वीकार कर लिया है। बीएसएनएल के करीब 1 लाख कर्मचारी वीआरएस के पात्र हैं, जिसमें कुल करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं। मौजूदा योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2020 है। किसी पात्र कर्मचारी को दी जाने वाली राशि उस कर्मचारी के पूरे हुए हर साल के 35 दिन के वेतन के बराबर राशि और शेष बचे साल के हर साल के वेतन के 25 दिन के बराबर वेतन शामिल है।

एमटीएनएल के पिछले 10 साल में 9 साल घाटा हुआ है और कंपनी 2010 से घाटे में चल रही है। दोनों कंपनियों पर कर्ज 40,000 करोड़ रुपये है।

सरकार को नॉमिनल जीडीपी में सुधार की आस

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 1 जनवरी

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 2019-20 के अपने संशोधित अनुमान के मुकाबले 2020-21 के लिए नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 10.5 फीसदी रहेगी। यह आंकड़ा नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट में दिया गया है।

रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को जारी किया। इसमें 2020-21 के लिए नॉमिनल जीडीपी 227 लाख करोड़ रुपये का रहने का अनुमान जताया गया है। जबकि 2019-20 के लिए अनुमान फिलहाल 205.37 लाख करोड़ रुपये नजर आ रहा है जबकि इससे पहले के बजट अनुमान में यह 211 लाख करोड़ रुपये रहा था।

रिपोर्ट में 2024-25 के लिए नॉमिनल जीडीपी 365.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए 2020-21 से 2024-25 तक औसत नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर 12.2 फीसदी सालाना रखने की जरूरत होगी।

दरअसल, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए गणितीय अनुमान से नॉमिनल जीडीपी की संभावित वृद्धि क्रमशः 12.6 फीसदी, 12.8 फीसदी और 13 फीसदी है। यदि इन वर्षों में औसतन 4 फीसदी की महंगाई दर का भी अनुमान लगाएं तो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 8 फीसदी की उच्च स्तर पर हो सकती है जो कि काफी महत्त्वाकांक्षी नजर आता है।

पाइपलाइन में 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 23 क्षेत्रों की परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिनके लिए अगले पांच वर्ष में केंद्र और राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र से रकम मुहैया कराई जाएगी। अब तक कुल नियोजित निवेश 102 लाख करोड़ रुपये का है जो अगले कुछ हफ्तों में 105 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है। परियोजनाओं में से 39 फीसदी का क्रियान्वयन केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाएगा जबकि 22 फीसदी परियोजनाएं निजी क्षेत्र पूरा करेंगे। सरकार उम्मीद कर रही है कि 2024-25 तक निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक हो जाएगी। पाइपलाइन में केंद्र, राज्यों, निजी क्षेत्र, सरकारी कंपनियों के साथ साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की पुरानी और नई परियोजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक कुछ 42.7 लाख करोड़ रुपये (43 फीसदी) की परियोजनाएं क्रियान्वयन के अंतर्गत हैं, 32.7 लाख करोड़ रुपये (करीब 33 फीसदी) की परियोजनाएं कतार में हैं और 19.1 लाख करोड़ रुपये (करीब 19 फीसदी) की परियोजनाओं पर काम हो रहा है।

पहचान किए गए क्षेत्रों में परंपरागत बिजली और अक्षय ऊर्जा, रेलवे, सड़क, शहरी विकास, सिंचाई, उड्डयन, शिक्षा और स्वास्थ्य है।

सरकार का बुनियादी ढांचे पर खर्च और नॉमिनल जीडीपी

वित्त वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बुनियादी ढांचा*	3.54	3.77	4.58	5.56	6.76	8.21	9.97
बजट मदद	1.39	1.53	1.86	2.25	2.74	3.33	4.04
जीडीपी प्रतिशत**	0.73	0.74	0.82	0.89	0.96	1.03	1.11
नॉमिनल जीडीपी	190.1	205.37	227.0	254.27	286.42	323.25	365.49

*केंद्र सरकार का कुल पूंजी आवंटन **जीडीपी के प्रतिशत में बजट समर्थन
सभी आंकड़े लाख करोड़ रुपये में, जब तक विशेष रूप से उल्लेख न हो
वित्त वर्ष 19 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान हैं, वित्त वर्ष 2020 के आंकड़े हाल के अनुमान, अन्य वर्षों का अनुमानित आंकड़ा
स्रोतः नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट

बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

भाषा
नई दिल्ली, 1 जनवरी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऋण की एक कथित धोखाधड़ी के मामले में विशाखापत्तनम निवासी एक व्यक्ति व उसके परिवार की 51 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है।

एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां कुमार पप्पू सिंह, उसके परिवार तथा उनकी कंपनियों से जुड़ी हैं। इनमें मछली पालन टंकियां, पॉल्ट्री फॉर्म और बैंक बैलेंस शामिल हैं। ईडी ने कहा कि यह मामला मछलीपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी से लाभ उठाने के एक आरोप में आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों, कुछ ऋण प्रदाताओं तथा अन्य के खिलाफ सीबीआई की दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। ईडी ने कहा कि सिंह ने 87 कर्जदारों के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लिया। इन लोगों में उसके परिजन, कर्मचारी व अन्य परिचित लोग शामिल हैं। एजेंसी ने कहा, 'ऋण की राशि को अवैध तरीके से कर्ज लेने वालों के खातों से सिंह व उसकी कंपनियों के खातों में हस्तांतरित किया गया।'

बीएस सूडोकू 3628

			2					
7	8	2			6		5	
	1			3				
4					1		2	5
	9	1				3	7	
2	6		8					4
				2			3	
	2		1			4	6	9
					3			

परिणाम संख्या 3627

6	2	8	1	7	4	9	3	5
5	4	7	9	3	6	8	1	2
3	1	9	2	8	5	4	7	6
1	3	4	8	6	9	2	5	7
8	5	6	7	1	2	3	9	4
7	9	2	4	5	3	1	6	8
2	7	5	3	9	8	6	4	1
9	8	1	6	4	7	5	2	3
4	6	3	5	2	1	7	8	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2185/2190, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4650/4700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 1575/1625, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1650/1700,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2210/2220, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1450, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1530, फ्लैक 1465, डीएमओ 1062, टरपीन लैस बोल्ड 1560

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1350/1410, खुरपा 1250/1290, चाकू 1250/1330, रसकट 1020/1040, शक्कर 1380/1410, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290,

हापुड़
गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1300/1390, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4650, खलः सरसों 2350/2450, बिनौला 2550/2700, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाजः चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2240/2250, मक्की 2250/2275, बाजरा 1940/1945, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3900/3950, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 4890/4900,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2100/2125, ग्वार 3950/4000, जौ 2190/2200,

जोधपुर
गेहूं 2100/2150, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4600/4700, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4150/4200, ग्वारगम 7800/7900, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4300/4400, काबली चना 5000/6000, मूंग 6400/6500,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)131, राइसब्रान (अखाद्य) 128, खल सरसों 2100, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1350,

लुधियाना
दाल-दलहनः राजमां चित्रा 7500/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8800/9500, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावलः बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5550, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धानः शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4050/4080, हरियाणा 4030/4040, राजस्थान 3950/4030, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2600/2700, सरसों खल 2250/2260,

फाजिल्का
गेहूं 2245/2250, सरसों 4650/4750 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4150, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5400/5500, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2700/2750,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2260/2270, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2500/2525, दाल उड़द छिलका 9500/10900, चना देशी 5200/5300, दाल चना 5500/5700, काबली चना 5300/6200, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600, चीन 7900/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2230/2240, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5150/5250, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 39000/3950, जौ 1775/1780, सरसों 4350/4400, मूंग 6500/6700, गेहूं 2150/2160,

जींद
जीएसटी अतिरिक्तः गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1100/1110, मैदा 1190/1200, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्तः सरसों 4450/4500, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2800/3400, सरसों तेल 9650/9700, गेहूं 2200/2225, ग्वार 3950/4000, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 272

असरदार फसल बीमा

मोदी सरकार अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमबीएफबीवाई) की समीक्षा करने जा रही है। यह किसानों का फसल जोखिम कम कर उन्हें सही मायने में फायदा पहुंचाने की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है। हालांकि योजना की समीक्षा के लिए मंत्री समूह जैसा उच्चस्तरीय पैनल बनाने की जरूरत पर बहस हो सकती है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समूह में गृह मंत्री और कुछ अन्य मंत्री भी शामिल हैं। वैसे कृषि विशेषज्ञों, किसानों, बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को इस समीक्षा पैनल में रखा जाता तो बेहतर होता। पीएमएफबीवाई के वर्ष 2016 में आगाज के कुछ समय बाद से ही इसकी पुनर्संरचना एवं समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी लेकिन सरकार को इस दिशा में कदम उठाने में समय लगा। फसल बीमा की तमाम पुरानी योजनाओं से बेहतर होने के बावजूद यह योजना अंतर्निहित संरचनात्मक, वित्तीय एवं लॉजिस्टिक खामियों के चलते किसी भी हितधारक को प्रभावित कर पाने में नाकाम रही।

इस मोर्चे पर सर्वव्यापी अंसतुष्टि इस बात से जाहिर होती है कि तीन प्रमुख कृषि राज्यों- आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार ने इस योजना से खुद को अलग कर लिया है। कम-से-कम तीन अन्य राज्य- कर्नाटक, गुजरात एवं ओडिशा भी ऐसा करने की सोच रहे हैं। इन राज्यों का मानना है कि योजना से होने वाले लाभों की तुलना में इसके संचालन की लागत कहीं अधिक है लिहाजा वे किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक तरीके आजमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चार निजी बीमा कंपनियों ने भी इस योजना को घाटा उठाने वाला धंधा बताते हुए खुद को अलग कर लिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि कई अन्य बीमा कंपनियों के भी इससे अलग होने के आसार हैं। हालांकि आम धारणा यही है कि सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बीमा कंपनियों के पास जा रहा है। किसानों को भी यह योजना अधिक भा नहीं रही है। वैसे किसानों को रबी फसलों के लिए महज एक फीसदी, खरीफ फसलों के लिए 1.5 फीसदी और वाणिज्यिक फसलों के लिए पांच फीसदी प्रीमियम ही देना होता है।

इस योजना के डिजाइन में एक बड़ी खामी यह है कि इसमें योजना के व्यय (यानी सब्सिडी) का बोझ राज्यों को केंद्र के साथ आधा-आधा उठाना है। राज्यों के हिस्से का फंड जारी करने में चूक होने से बीमा दावों के त्वरित निपटान की बीमा कंपनियों की क्षमता भी प्रभावित होती है। फसलों को अधिसूचित करने, बुआई का रकबा और बीमा योग्य अधिकतम राशि तय करने का अधिकार राज्यों को देने से भी इस योजना की नाकामी का रास्ता तैयार हुआ है। राज्य अक्सर अपने वित्तीय बोझ को कम रखने के लिए सीमा को काफी कम रखते हैं जिससे उत्पादकों के लिए योजना की उपयोगिता कम हो जाती है। कर्जदारों की फसल का बीमा करने की बैंकों को दी गई मंजूरी भी योजना की एक बड़ी समस्या है।

बैंक अमूमन कर्ज के बरक्स बीमित राशि का समायोजन कर लेते हैं जिससे किसान असहाय हो जाते हैं। बीमित उत्पादक किसानों को अक्सर लेनदेन के विवरणों के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। भले ही फसलों को हुए नुकसान के त्वरित आकलन के लिए इस योजना में तकनीक खासकर सैटेलाइट इमेजिंग के इस्तेमाल की परिकल्पना की गई है लेकिन अभी तक इसके वांछित परिणाम नहीं रहे हैं। नुकसान के आकलन के लिए राज्य सरकारें जिन तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, वे समय-साध्य एवं अपारदर्शी होने से भरोसे का संकट पैदा होता है। ऐसे में अचरज नहीं है कि किसानों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उन्हें या तो मुआवजा अपर्याप्त मिलता है या मिलता ही नहीं है। अगर मंत्री समूह इन सभी बिंदुओं एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर ठीक से ध्यान देता है तो पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए वरदान बनाने की उम्मीद बंधेगी।

अजय मोहंती

धरती को बचाने के तीन जरूरी कदम

जलवायु वार्ताओं को सार्थक बनाने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे। पिछली गलतियां स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की मंशा के बगैर ऐसा होना मुश्किल है। बता रहे हैं अरुणाभ घोष

किसी समस्या के समाधान के लिए पहले हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मैड्रिड जलवायु सम्मेलन में चर्चा के लिए जुटे तमाम वार्ताकार ऐसा करने में नाकाम रहे। पिछले किसी भी वार्षिक जलवायु सम्मेलन से अधिक समय तक चलने के बावजूद मैड्रिड सम्मेलन किसी समझौते के बगैर ही समाप्त हो गया। पेरिस समझौता असल में सुलह का एक तरीका था जिसमें हरेक के लिए कुछ-न-कुछ दिया गया था। इस साल के 'कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज' (सीओपी-25) में किसी के लिए भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। मुद्दा जलवायु वार्ताओं की नाकामी नहीं है। असली समस्या यह है कि हम एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। किसी भी रिश्ते में भरोसा बहाल करने की शुरुआत ईमानदारी से होनी चाहिए और फिर पिछली गलतियों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। इससे साथ मिलकर काम करने के वादों का रास्ता बनेगा। धरती बचाने के घटनाक्रम को तीन दृश्यों में यहां पेश किया जा रहा है।

पहला कदम: सच्चाई। ईमानदारी एक गुण है और विश्वसनीयता एक प्रतिष्ठा है। जलवायु सम्मेलनों में किए गए वादे विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि दो कड़वे सच के बारे में ईमानदारी की कमी है। जलवायु पहले ही बदल चुकी है और उठाए जा रहे कदम पर्याप्त होने के आसपास भी नहीं हैं। विश्व का तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में कम-से-कम 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की राह पर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने हाल में कहा है कि पेरिस समझौते की मंशा के अनुरूप अगर वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक ही सीमित रखना है तो 2020-30 के दौरान ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में हर साल 7.6 फीसदी गिरावट लानी होगी।

इस सबूत के बरक्स ऐसी अपेक्षा है कि हरेक देश को आकांक्षाएं बढ़ानी होंगी। लेकिन यह संकल्पना दोषपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई शीघ्रता नहीं है। अगर एक देश वर्ष 2050 तक विशुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा करता है तो उसे जलवायु नेता माना जाता है। इस दिशा में जल्द काम नहीं करने या उत्सर्जन कटौती की योजना पहले नहीं बनाने पर फटकार नहीं है। ऐतिहासिक रूप से बड़े प्रदूषक देशों के कदमों में देरी से दुनिया की बहुसंख्यक आबादी के लिए बाकी कार्बन बजट सिकुड़ता जाता है। अगर देश बुनियादी कार्बन गुणा-गणित को लेकर बेईमान बने रहते हैं तो दीर्घकालिक रणनीति विश्वसनीय नहीं है।

पहले कदम का अंत नैतिक सच्चाई के नाटकीय प्रदर्शन के साथ होना चाहिए: दीर्घकालिक रणनीतियों और बढ़ी हुई महत्त्वाकांक्षा रखने वाले देशों को यह भी बताना चाहिए कि उनकी योजनाएं किस हद तक फ्रंटलोडेड हैं और उन पर अमल करने के लिए किस तरह के नियंत्रण एवं संतुलन रखे गए हैं?

दूसरा कदम: निवारण। भूलने से कहीं अधिक आसान होता है माफ करना। अमीर देश 2020 से पहले के अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। किसी भी विकसित देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर किए गए दोहा समझौते के हिसाब से अपनी महत्त्वाकांक्षाएं ऊंची नहीं की। इसका मतलब है कि वर्ष 2020 तक जरूरी उत्सर्जन कटौती नहीं की गई। इसके अलावा वर्ष 2020 तक जलवायु मद में 100 अरब डॉलर के वित्तपोषण का वादा पूरा करने के बजाय 2013-18 के दौरान राहत के लिए बहुपक्षीय जलवायु कोष ने केवल 10.4 अरब डॉलर की ही मंजूरी दी और अनुकूलन फंडिंग केवल 4.4 अरब डॉलर रही।

तीसरी चुनौती यह है कि स्वच्छ विकास व्यवस्था के तहत चार अरब अनबिके प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां हैं। उनके लिए भुगतान नहीं करने से कार्बन बाजार में भरोसा कम होता है। उन्हें आगे ले जाने से 2020 के बाद कार्बन बाजार में क्रेडिट की भरमार होगी और आगे चलकर ऑफसेट की कीमत कम हो जाएगी।

अतीत को भुलाया नहीं जा सकता है और सभी पक्ष 1 जनवरी 2021 से लागू हो रहे पेरिस समझौते पर अमल पर ही ध्यान नहीं दे सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैरमहत्त्वाकांक्षी कार्य, अपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता और अनबिके कार्बन क्रेडिट के मुद्दे पर यह सवाल बदस्तूर कायम है कि 'मुझे कैसे पता कि तुम मुझे दोबारा मूर्ख नहीं बनाओगे?'

दूसरा कदम पिछली शिकायतों को दूर करने की मांग करता है। सितंबर 2020 तक विकसित देशों को हामी भरनी चाहिए कि 2020 से पहले की प्रतिबद्धता और परिणामों के बीच के फासले को वे 2020-पश्चात के अपने संकल्प में घरेलू स्तर पर पूरी तरह आत्मसात कर लेंगे। इसके अलावा विकसित देशों को अनबिके सीडीएम क्रेडिट को एकमुश्त समाधान के जरिये चुका देना चाहिए। दिवालिया प्रक्रिया की तरह रियायती दर पर मोलभाव करना व्याकुलता से भरा होगा। लेकिन कोई भी तय मूल्य निम्न-कार्बन निवेश के एवज में संभावित लाखों करोड़ डॉलर की तुलना में बहुत छोटा ही होगा। ऐसे समाधान से 2020-पश्चात के उत्सर्जन कारोबार बाजार की सच्चाई बनी रहेगी जैसा जिक्र पेरिस समझौते की धारा 6 में है। ये दोनों ही कदम सरकारों और बाजारों के प्रति भरोसे को खासा बढ़ा सकते हैं।

तीसरा कदम: नवीनीकरण। सभी संबंधों को दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए। वित्त और तकनीक पर नए सिरे से ध्यान देकर सामूहिक जलवायु प्रयास के वादे का नवीनीकरण संभव है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पास निम्न-कार्बन ढांचे को छलांग लगाकर पार करने का मौका है। चीन, भारत और मैक्सिको जैसे देश नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर पहले से ही इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वित्त की लागत संस्थागत निवेशकों को आशंकित जोखिमों के चलते निषेधकारी बनी हुई है। वित्त पर एक नए करार की जरूरत है। वैश्विक वित्त को जलवायु जोखिम एवं निवेश जोखिम की तुलना में जोखिमपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, प्रीमियम कीमत वास्तविकता दर्शाने वाली होनी चाहिए न कि धारणा। तमाम जोखिमों को कम करने के लिए सार्वजनिक धन के छोटे हिस्से का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इसी तरह तकनीक पर एक नया सौदा होने से विभिन्न तरह की तकनीकों के लिए मिलजुलकर प्लेटफॉर्म बनाए जा सकेंगे। पहला, ऊर्जा-सक्षम उपकरण और वितरित बिजली को बढ़ावा देने वाले वाणिज्यिक प्रायोगिक परियोजना के जरूरतमंद। दूसरा, किफायती सौर उपकरण, ऊर्जा भंडारण और कम कार्बन वाली कूलिंग तकनीकों के लिए अहम शुरुआती निवेश के आकांक्षी। और तीसरा, अधिक जोखिम लेकिन ऊंची संभावनाओं से भरपूर तकनीकों के लिए फंड एवं वैज्ञानिक प्रतिभा को इकट्ठा करना (उद्योग के लिए नवीन ऊर्जा से निकला हाइड्रोजन, कार्बन भंडारण एवं उपयोग और सौर विकिरण प्रबंधन)।

शेक्सपियर की वह पंक्ति अच्छी सलाह देती है कि 'सबसे प्रेम करो, कुछ पर भरोसा करो और किसी के साथ भी गलत मत करो।' नवंबर 2020 में एक बार फिर सभी देश ग्लास्गो में इकट्ठा होकर जलवायु मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमें अपनी धरती से प्यार करना होगा, पिछली गलतियां ठीक करनी होंगी और कदम-दर-कदम भरोसा बहाल करना होगा। 'अंत भला तो सब भला' कहावत हमें यही सलाह देती है। ईमानदार एवं प्रभावी जलवायु प्रयास के लिए हम यह बात कह पाने से अभी बहुत दूर हैं।

(लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)

बहु-संस्कृतिवाद को उभरते उप-राष्ट्रवाद से गंभीर खतरा

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर मचा घमासान इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करता है कि सरकार लंबे समय से चली आ रही देश की बहु-संस्कृतिवाद की परंपरा के प्रति गंभीर नहीं है। देश को 'मुस्लिम मुक्त' बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की योजना ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है, जो देश के बहु-संस्कृतिवाद के आसन्न खतरों की महज एक झलक भर है। सीएए और एनआरसी पर हो रहा विरोध केवल एक जगह सीमित नहीं है और इसने देश में 'उप-राष्ट्रवाद' की ज्वाला भड़का दी है। अगर यह स्थिति जल्द नियंत्रित नहीं गई तो देश के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सीएए और एनआरसी को लेकर मुसलमानों में अंसुष्टि से देश में विरोध प्रदर्शन का स्वर तेज होता गया और देश के कई क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ सड़क पर उतर आए। 27 प्रतिशत आदिवासी आबादी वाले झारखंड के मतदाताओं ने एनआरसी प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जता दी है, खासकर नागरिकता से जुड़े प्रमाण के लिए ऊंचे मानदंड तय किए जाने से लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों को खासकर इस बात का डर सता रहा है कि सीएए और एनआरसी के बाद बंगाली हिंदुओं के आने से उनकी अपनी विशेष पहचान खत्म हो जाएगी। जनवरी में विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया था और कानून के नए प्रारूप में इन राज्यों की चिंताएं दूर करने के लिए बदलाव किए गए थे। इस तरह, पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्र इस कानून की जद से बाहर रखे गए थे।

सीएए और एनआरसी पर विभिन्न समूहों एवं समुदायों ने आपत्ति जताई है। पूर्वोत्तर भारत में हिंदू एवं मुस्लिम बंगाली समुदाय स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं और खासकर असम में लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ दोबारा फूट पड़ा है। सिक्किम के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और अब राजनीति में उतरे बाईचुंग भूटिया ने ऐसी चिंता जताई है कि उनके राज्य की संस्कृति पर हमला किया जा रहा है। प्राय: सभी लोग बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब भाषा संस्कृति सीमाएं लांघती हैं तो जातिगत हिंसा का रण क्षेत्र तैयार हो जाता है। भाजपा ने बहुत पहले ही सभी मुसलमान परस्तों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी है। अब अगर भाजपा यह मांग करने लगे कि सभी बंगालियों को बांग्लादेश जाना चाहिए तो इसमें किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

इस तेजी से उभरते उप-राष्ट्रवाद के साथ जुड़ी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अर्थव्यवस्था में अगर सुधार नहीं हुआ और रोजगार की संभावनाएं कम हुईं तो इसमें और तेजी आ सकती है। पिछली बार के वैश्विक वित्तीय संकट से यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी है और इसके लिए सरकार को इतिहास के पन्ने भी पलटने की जरूरत नहीं है। देश ने 2008 में वह नजारा देखा था जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) के लोगों के डर से उत्तर प्रदेश और बिहार के भयभीत लोग किस तरह देश की वित्तीय राजधानी मुंबई से पलायन कर रहे थे।

इसके बाद 2012 में भारत की अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ी थी तो उस समय भी पूर्वोत्तर के लोग भारत का तथाकथित 'सिलिकन वैली' माने जाने वाले सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) केंद्र बेंगलूरु से खदेड़े जा रहे थे। इस साल मई में भी कई वीडियो सामने आए, जिनमें राजनीतिक लफंगे कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारियों को पीट रहे थे और उन्हें आतंकवादी तक कहा जाने लगा था। अगस्त में सरकार ने जम्मू कश्मीर का संविधान प्रदत्त विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और मोटे तौर पर देश के ज्यादातर हिस्सों में इसे लेकर संतोष का भाव देखा गया। गैर-कश्मीरी मानने लगे कि अब वह भी 'धरती के स्वर्ग' में जमीन-मकान आदि खरीद पाएंगे। 5 अगस्त से यह पूरा क्षेत्र सुरक्षा घेरे में हैं और धीरे-धीरे इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। अक्टूबर में श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय निवेश सम्मेलन आयोजित होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया और यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

आंध्र प्रदेश में भी उप-राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के मौजूदा और नए उद्योगों-सार्वजनिक, संयुक्त उद्यम-सभी के लिए स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है। 2014 में विभाजन के बाद अस्तित्व में आया आंध्र प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने यह दिशानिर्देश दिया है। अब दूसरे राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में 2008 में राज ठाकरे के डर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के पलायन के बाद छोटी एवं मझोली फैक्टरियां खाली हो गई थीं और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा सहित दूसरे बड़े उद्योगों को कल-पुर्जों की आपूर्ति थम गई थी। बेंगलूरु से पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन के बाद हजारों छोटे कारोबार खासकर तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र कर्मचारी विहीन हो गए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि राज्य के गृहमंत्री को लोगों का डर दूर करने स्वयं रेलवे स्टेशनों के चक्कर लगाने पड़े।

राज्य में निवेश करने के आतुर निवेशकों से रेड्डी ने बात की होती तो वे उन्हें इस स्थानीय राजनीति के नुकसान के बारे में पता चलता। कारोबारों, खासकर जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, को सामाजिक एवं क्षेत्रीय पक्षों से ध्यान हटाकर प्रतिभा को वरीयता देनी चाहिए। इस तर्क को शायद ही कोई आसानी से स्वीकार करेगा कि आंध्र के लोग देश के दूसरे हिस्सों से अधिक प्रतिभावान हैं, इसलिए उन्हें विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एमएनएस को इस तरह की सोच का नुकसान उठाना पड़ा है। वहां निजी क्षेत्र लागत के लिहाज से किफायती मानव श्रम को अधिक तरजीह दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री के हाल के भाषण से फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिकता पर बहस किस दिशा में बढ़ रही है।

कानाफूसी

अंदरूनी संकट

हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को राज्य विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर लखनऊ के एक सांसद ने लखनऊ पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मोहनलालगंज आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर ने राज्य की राजधानी में तेजी से बढ़ते अपराधों की संख्या के लिए राज्य पुलिस के गैर पेशेवर रवैये को दोषी ठहराया है। किशोर का दावा है कि कई मामलों में पुलिस सही तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है और कई मौकों पर जांच में तेजी लाने के अनुरोध के साथ उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। एक ओर उनकी नाराजगी ने भाजपा की राज्य इकाई को अस्थिर कर दिया है तो वहीं विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर अपने हमले तेज करने के लिए किशोर के आरोपों का सहारा लिया।

वाटरप्रूफ घड़ी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने विपक्षी पार्टियों के तौर-तरीकों को समझाने के लिए एक रोचक तथ्य से इसकी समानता की। उन्होंने कहा, 'हमारे स्कूल के दिनों में वाटरप्रूफ घड़ी का चलन था। इस तरह की घड़ियों में पानी अंदर नहीं जा पाता। कुछ इसी तरह सीएए का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों का दिमाग भी 'नॉलेज प्रूफ' और 'जानकारी प्रूफ' हो गया है।' नागरिकता (संशोधन) कानून में पहली बार देश में नागरिकता के लिए धर्म को आधार बनाया गया है। सरकार का कहना है कि अगर तीन मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यक धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आते हैं तो सरकार उन्हें मदद मुहैया कराएगी। आलोचकों का कहना है कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव फैलाने के लिए लाया गया है और इससे संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

आपका पक्ष

जल संरक्षण के लिए बनें जिम्मेदार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अटल जल योजना का शुभारंभ किया जिसका मकसद भूजल स्तर में गिरावट को रोकना है। हम सभी प्राणियों के लिए जल सबसे महत्त्वपूर्ण है। इसके संरक्षण के लिए सदैव एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह प्रयास करते रहना चाहिए। आजकल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हवा में कुछ जमे हुए पानी के कण और नमी मिली थी। मानव की भूलों का ही परिणाम है कि आज धरती पर जल संकट खड़ा हो गया है। लगातार बढ़ता प्रदूषण और जल संचयन का अभाव इसके मुख्य कारण हैं। प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ किया और इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी धरती के जल स्रोत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह बढ़ता हुआ जल प्रदूषण है। नदियों में बेरोकटोक प्लास्टिक, कूड़ा-कचरा डालना, कारखानों का गंदा पानी

नदियों में डालना आदि की वजह से नदी प्रदूषित हो गया है। नदियों का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। अगर इसी प्रकार हम नदियों, तालाबों आदि को प्रदूषित करते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी पर जल एक असीम प्राकृतिक संसाधन है जो पुन:चक्रण द्वारा बनता है। लेकिन स्वच्छ और पीने

भूजल संरक्षण के लिए हमें पानी की बचत करने की आवश्यकता है

योग्य पानी हमारी प्रमुख आवश्यकता है जिसे हमारे सुरक्षित स्वस्थ जीवन के लिए बचाया जाना चाहिए। पानी की असली कीमत तो वही व्यक्ति बता सकता है जो रेगिस्तान की तपती धूप से निकल कर आया हो। इसलिए जल संरक्षण को सभी व्यक्तियों को समझना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा।

अनु मिश्रा, सीवान

भूत विद्या को लेकर विवादों में बीएचयू

इन दिनों देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि किसी न किसी मुद्दे पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन जगहों में नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर विरोध चल रहा है। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) अपने पाठ्यक्रम में भूत विद्या पढ़ाए जाने को लेकर चर्चा में है। दरअसल बीएचयू के विज्ञान संस्थान के अंतर्गत आने वाले आयुर्वेद संकाय ने अपने पाठ्यक्रम में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जिसका सिलेबस भूत विद्या पर पीएचडी कर चुके प्रोफेसर वीके द्विवेदी ने तैयार किया है। भूत विद्या चिकित्सा के अंतर्गत आने वाला अष्टांग आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद के आठ प्रकार का ही एक भाग है। इंटरनैशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एवं फार्मा रिसर्च के अनुसार संपूर्ण कोर्स यजुर्वेद पर आधारित है जिसमे सुश्रुत (सर्जरी के पितामह) ने भूत विद्या को आयुर्वेद की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारी जिसे दूर दराज के इलाकों में भूत बाधा बता कर बिरादरी से निकाल दिया जाता है, ऐसी सभी भ्रांतियों को खत्म करने और साइको सिमेंटिक अर्थात मनोदैहिक रोगों से निजात पाने के लिए बनाया गया है। पाठ्यक्रम में अवसाद, तनाव और कोलाइटिस जैसे मनोविकार से मुक्ति पाने के लिए वैज्ञानिक और चिरस्मत विद्या का प्रयोग किया जाएगा।

गरिमा सिंह, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

बीते साल सीमेंट की मांग रही कमजोर

सीमेंट की मांग में वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में सुधार के आसार हैं

अमृता पिल्लई
मुंबई, 1 जनवरी

मंदी का भी पड़ा असर

- अप्रैल-सितंबर के बीच पूरे भारत में सीमेंट की बिक्री वृद्धि कमजोर पड़ कर 2 से 4 प्रतिशत के दायरे में रह गई
- सीमेंट क्षेत्र को कैलेंडर वर्ष के साथ साथ वित्त वर्ष का समापन सपाट मांग वृद्धि के साथ रहने का अनुमान है
- विश्लेषकों को 2020 के मॉनसून के बाद ही हालात में कुछ सुधार आने की संभावना है

सीमेंट क्षेत्र में कोई बड़ा सुधार दर्ज नहीं किए जाने की वजह से पिछले साल इसकी मांग में वृद्धि की रफ्तार काफी हद तक प्रभावित हुई। निकट भविष्य में मांग वृद्धि में बड़ा सुधार नहीं दिखने के अनुमान के साथ विश्लेषकों को 2020 के मॉनसून के बाद ही हालात में कुछ सुधार आने की संभावना है। अप्रैल और सितंबर के बीच पूरे भारत में सीमेंट की बिक्री वृद्धि कमजोर पड़कर 2 से 4 प्रतिशत के दायरे में रह गई। सीमेंट क्षेत्र के लिए कैलेंडर वर्ष के साथ साथ वित्त वर्ष का समापन सपाट मांग वृद्धि के साथ होने का अनुमान है।

जेके लक्ष्मी सीमेंट के पूर्णकालिक निदेशक शैलेंद्र चोकसी ने कहा, 'पहली तिमाही में आम चुनाव, और उसके बाद, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से मांग खपत पर प्रभाव पड़ा और कैलेंडर वर्ष के बाद के समय में भी मांग में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा।'

भारत में सीमेंट की मांग पूरे वित्त वर्ष के लिए 5 से 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया था। यह अनुमान दो वर्षीय मजबूत वृद्धि को देखते हुए लगाया गया। लेकिन भारत की सीमेंट मांग वृद्धि की रफ्तार अप्रैल 2019 से कमजोर पड़ गई।

अल्ट्राटेक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अतुल डग्गा ने कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों के अवसर पर कहा, 'मार्च 2019 तक पिछली 8-10 तिमाहियों में इस उद्योग की राह में अनिश्चितता देखने को मिली। चुनाव के बाद मंदी की आशंका जताई गई थी, लेकिन इस तरह की भारी गिरावट को लेकर हमें आश्चर्य हुआ है।' डग्गा ने दूसरी तिमाही में सीमेंट की मांग में गिरावट 2-2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था, क्योंकि सिर्फ उत्तर भारत के सीमेंट बाजार में सकारात्मक वृद्धि दर दिखी। विश्लेषकों का कहना है कि मांग वृद्धि अब 2020 में मॉनसून के बाद ही सुधरने की संभावना है। रिलायंस सिक्योरिटीज में विश्लेषक बिनोद मोदी का कहना है, 'इस साल सीमेंट की मांग 5 से 6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नकदी पर दबाव, बुनियादी ढांचा विकास में सुस्ती और उसके बाद मॉनसून के लंबा खिंचने से सीमेंट की मांग प्रभावित हुई।'

उन्होंने कहा, 'मांग में बड़ा सुधार सिर्फ वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में ही आने की संभावना है।' जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों ने अपनी 22 नवंबर की रिपोर्ट में कहा, 'दो वर्षों तक तेजी दर्ज करने के बाद सीमेंट क्षेत्र में बिक्री वृद्धि धीमी रहने की आशंका है।' विश्लेषकों का कहना है, 'सड़क/सरकारी गतिविधियों के लिए ठेकों की धीमी रफ्तार और शहरी रियल एस्टेट निर्माण में लगातार सुस्ती को देखते हुए वर्ष 2020 की दूसरी छमाही से सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।'

अल्ट्राटेक जैसी कुछ कंपनियों को जल्द सुधार की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषकों ने 26 दिसंबर की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'हाल में मांग में सुधार आया है और मार्च 2020 की तिमाही में वृद्धि की संभावना बढ़ी है। देश में कुल मांग वित्त वर्ष 2021 में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत रहेगी और पूर्वी क्षेत्र में यह सालाना 10 प्रतिशत पर रह सकती है।' यह रिपोर्ट अल्ट्राटेक प्रबंधन के साथ बैठक में मिली जानकारी पर आधारित थी। पूरे भारत में सीमेंट की कीमतों में कमजोर रुझान बना हुआ है। जेएम फाइनैंशियल की शोध रिपोर्टों पर आधारित नवंबर 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सीमेंट कीमतें आठ महीने के दौरान या तो नीचे आईं या वे सपाट बनी रहीं।

अप्रैल-जून 2019 की अवधि में सीमेंट उद्योग का क्षमता इस्तेमाल भी प्रभावित हुआ। जून तिमाही में क्षमता इस्तेमाल 67 प्रतिशत पर था, जबकि सात तिमाहियों की वृद्धि के बाद बिक्री में 3-4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

सीमेंट क्षेत्र को पिछले दशक के ज्यादातर समय में कमजोर क्षमता उपयोग का सामना करना पड़ा। यस सिक्योरिटीज रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमेंट क्षेत्र के लिए आपूर्ति किल्लत वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 15.6 करोड़ टन सालाना हो गई जो वित्त वर्ष 2009 में 3.8 करोड़ टन थी। समान अवधि में क्षमता इस्तेमाल वित्त वर्ष 2009 के 80 प्रतिशत से घटकर 70 प्रतिशत रह गया।

चोकसी ने कहा, 'हमें इस उद्योग का क्षमता इस्तेमाल मौजूदा तीन-चार वर्षों में 67-68 प्रतिशत से सुधरकर 80-82 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।'

कच्चे और रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क में कटौती

एजेंसियां
नई दिल्ली, 1 जनवरी

- रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत किया गया
- कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत किया गया
- शुल्क कटौती आसियान समझौते और भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के तहत की गई

सरकार ने आज तुरंत प्रभाव से रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत और कच्चे पाम तेल (सीपीओ) पर आयात शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 37.5 प्रतिशत कर दिया। उद्योग ने सरकार के इस कदम का यह कहते हुए विरोध जताया है कि इससे घरेलू रिफाइनरों को नुकसान होगा।

इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह शुल्क कटौती आसियान समझौते और भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (आईएमसीईसीए) के तहत की गई है। इस कदम का विरोध करते हुए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने कहा कि आयात शुल्क में इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के बीच शुल्क का अंतर 10 प्रतिशत से घटकर 7.5 प्रतिशत रह गया है। सीईए के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने एक बयान में कहा कि इससे घरेलू पाम तेल रिफाइनिंग उद्योग और तिलहन किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमें इस बात का डर है कि इससे रिफाइंड पाम तेल आयात में इजाफा होगा और हमारे उद्योग की स्थापित क्षमता पर असर पड़ेगा जिससे परिणामस्वरूप रोजगार जाने की आशंका है।

लंबे समय बाद घरेलू तिलहन की बिक्री इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक स्तर पर होने लगी थी। उन्होंने कहा कि कम आयात शुल्क के कारण एमएसपी प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाएगा और तिलहन किसानों के उत्साह में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि देश का खाद्य तेल आयात अब उपभोग के 70 प्रतिशत भाग को छू रहा है। शुल्क में इस कटौती से उत्पादकता में कमी आएगी और यह घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने के सरकार के घोषित लक्ष्य के विपरीत होगा।

एसईए ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को भी मलेशिया और इंडोनेशिया की तरह किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। संगठन ने कहा कि इंडोनेशिया ने 1 जनवरी से कच्चे पाम तेल पर 50 डॉलर और रिफाइंड पाम तेल पर 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है। इसी तरह मलेशिया ने कच्चे पाम तेल पर 31 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है और रिफाइंड पाम तेल पर निर्यात शुल्क शून्य कर दिया है। इस तरह प्रभावी शुल्क अंतर मुश्किल से केवल 2.5 प्रतिशत ही है।

उद्योग के संगठन ने कहा कि हम सरकार से उचित कदम उठाकर कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के बीच शुल्क अंतर बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का अनुरोध करते हैं।

पान की खेती के लिए मिले बीमा

भाषा
औरंगाबाद, 1 जनवरी

औरंगाबाद के जालना और अन्य क्षेत्रों में पान पत्ते की खेती में कमी आई

महाराष्ट्र के संकटग्रस्त पान पत्ते की खेती करने वाले किसानों ने उन्हें बीमा कवच प्रदान किए जाने की मांग की है। उनका दावा है कि पर्याप्त वित्तीय जोखिमों के कारण पान की खेती लगभग बंद हो गई है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि औरंगाबाद के जालना और अन्य क्षेत्रों में पान पत्ते की खेती में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पान की खेती बीमा कवच की श्रेणी में नहीं आती है।

उन्होंने यह भी कहा कि बाजार में पान पत्ते की मांग घटने और इसकी खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता इसकी खेती के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। कुछ साल पहले तक, औरंगाबाद के जालना और जलगांव जिलों में पान की खेती की जाती थी।

किसानों ने कहा कि गेहूं, धान और मक्का जैसी अन्य फसलों के विपरीत पान की खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जालना जिले के भरत बद्रुक गांव के किसान तुलशीराम पयघन ने बताया, 'पान पत्ते की खेती के रकबे में कमी आई है क्योंकि फसल बीमा योजना उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय काश्तकारों ने इसे उगाना बंद कर दिया है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को सब कुछ खोना पड़ जाता है।'

जालना के एक और किसान ने दावा किया कि उनके क्षेत्र में बिक्री के लिए भेजे जाने वाले पान पत्ते की खेप वर्ष 2005 के प्रति सप्ताह चार ट्रक के मुकाबले घटकर अब एक मिनी ट्रक प्रति सप्ताह रह गया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में पान की खेती का रकबा वर्ष 2004 के 150 हेक्टेयर के मुकाबले 25 से 30 हेक्टेयर रह गया है।

दिसंबर में कोल इंडिया का उत्पादन सात प्रतिशत बढ़ा

भाषा
नई दिल्ली, 1 जनवरी

दिसंबर महीने में कोयला उत्पादन 7 प्रतिशत बढ़कर 5.8 करोड़ टन रहा

सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का दिसंबर महीने में कोयला उत्पादन 7 प्रतिशत बढ़कर 5.8 करोड़ टन रहा है। इससे पिछले कुछ महीनों से सीआईएल का कोयला उत्पादन लगातार घट रहा था। इससे पिछले साल के समान महीने में कोल इंडिया का उत्पादन 5.41 करोड़ टन रहा था।

कंपनी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि दिसंबर में कोयला उत्पादन नवंबर की तुलना में करीब 80 लाख टन अधिक रहा। नवंबर में यह 5.02 करोड़ टन था। अस्थायी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर की अवधि में कोल इंडिया का उत्पादन 38.83 करोड़ टन रहा है जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 41.24 करोड़ टन के आंकड़े से 5.83 प्रतिशत कम है। कोल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 66 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

दिसंबर तक कंपनी का 45.72 करोड़ टन के उत्पादन का लक्ष्य था जिससे वह चूक गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी आधिकारिक रूप से अपने उत्पादन आंकड़े जारी नहीं किए हैं।

सब्सिडी रहित गैस सिलिंडर 19 रुपये महंगा हुआ

भाषा
नई दिल्ली, 1 जनवरी

एलपीजी सिलिंडर का दाम भी 695 रुपये से बढ़ाकर 714 रुपये किया गया

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी के चलते विमान ईंधन (एटीएफ) के दाम में आज 2.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलिंडर भी 19 रुपये महंगा हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मूल्य के बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 1,637.25 रुपये किलोलीटर यानी 2.6 प्रतिशत बढ़कर 64,323.76 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी की वजह से दरों में लगातार दूसरे महीने वृद्धि की गई है। इससे पहले एक दिसंबर को एटीएफ के दामों में मामूली 13.88 रुपये किलोलीटर की वृद्धि की गई थी।

इस वृद्धि का बोझ पहले से नकदी संकट का सामना कर रही एयरलाइन कंपनियों पर पड़ेगा। इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलिंडर का दाम भी 695 रुपये से बढ़ाकर 714 रुपये कर दिया है।

यह लगातार पांचवां महीना है जब रसोई गैस के दाम में वृद्धि की गई है। रसोई गैस की कीमत 2019 से बढ़ाई जा रही है। पिछले पांच महीनों में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 139.50 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़े हैं। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रेल किराये और गैस सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की आलोचना की है और कहा है कि मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का नए साल का तोहफा दिया है।

ऊहापोह में फंसी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का क्या है भविष्य ?

दो घटनाओं ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने की भारत की योजना को संदेह के घेरे में ला दिया

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 1 जनवरी

- 6 करोड़ टन क्षमता और 44 अरब डॉलर की लागत वाली वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना की घोषणा जून 2018 में की गई थी
- इस परियोजना में सऊदी अरामको और अबूधाबी नैशनल ऑयल कंपनी के पास 50 फीसदी हिस्सेदारी है
- शेष हिस्सेदारी देश की तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है
- भारत अपनी जरूरत का 18 फीसदी कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है, इस उभरते बाजार में कंपनी को अपनी पहुंच मजबूत करने में मदद मिलेगी

दो घटनाओं ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने की भारत की योजना को संदेह के घेरे में ला दिया है। 6 करोड़ टन क्षमता और 44 अरब डॉलर की लागत वाली वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना की घोषणा जून 2018 में की गई थी। इस परियोजना में सऊदी अरामको और अबूधाबी नैशनल ऑयल कंपनी (एडनॉक) के पास 50 फीसदी हिस्सेदारी तथा शेष हिस्सेदारी देश की तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पास है।

उसके बाद गत अगस्त में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने केमिकल और रिफाइनिंग कारोबार की 20 फीसदी हिस्सेदारी 15 अरब डॉलर में सऊदी अरामको को बेचने की योजना की घोषणा की। यह बिक्री कंपनी की मार्च 2021 तक अपना कर्ज समाप्त करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। नवंबर 2019 में सरकार ने कहा कि वह बीपीसीएल में अपनी 53.29 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इसे खरीदने की इच्छुक कंपनियों में सऊदी अरामको के अलावा फ्रांसीसी कंपनी टोटाल, बीपी पीएलसी, वेदांता, एक्सॉन मोबिल, आरआईएल और अदाणी समूह शामिल हैं।

इन बातों ने वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी की संभावनाओं को धूमिल किया है क्योंकि अब बहस इस बात पर हो रही है कि एक नई रिफाइनरी शुरू करना बेहतर होगा या पहले से चली आ रही रिफाइनरी को ठीक माना जाए? दूसरे शब्दों में कहें तो बीपीसीएल को वेस्ट कोस्ट की तुलना में खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प माना जा रहा है।

हालांकि विशेषज्ञों की राय ऐसी नहीं है क्योंकि बीपीसीएल की परिसंपत्ति का अवमूल्यन हो रहा है। वह 20 वर्ष पहले वर्ष उत्कृष्टतम स्तर पर रही होगी। एक वैश्विक सलाहकार कंपनी के वरिष्ठ विशेषज्ञ की मानें तो नई रिफाइनरी के निर्माण में नई तकनीक शामिल होती है और साथ ही कच्चे तेल का प्रबंधन और उत्पादन आदि अधिक किफायती होता है। यह भविष्य की दृष्टि से बेहतर तैयारी होती है।

यह बात सैद्धांतिक तौर पर ठीक है लेकिन चूंकि यह भारत है इसलिए वेस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट पहली ही बाधा पर अटक गया- यानी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण। रत्नागिरि क्षेत्र में भारी विरोध के कारण इस संयुक्त उपक्रम को रायगड जिले में 140 किमी उत्तर में स्थानांतरित करना पड़ा। कच्चे तेल की तीन यूनिट वाले रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल परिसर के लिए कम से कम 15,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। साथ ही इसे समुद्र के निकट भंडारण और बंदरगाह की सुविधा भी चाहिए। स्थानीय लोगों के भारी विरोध के कारण इनमें से कोई मांग पूरी नहीं हो सकी है।

अब यह परियोजना राजनीतिक दिक्कतों में उलझ सकती है। शिव सेना जो रत्नागिरि में जमीन से जुड़े विरोध का नेतृत्व कर रही थी, वह अब महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चला रही है। ऐसे में रायगड में जमीन अधिग्रहण करना भी मुश्किल हो सकता है। इस संयुक्त उपक्रम यानी रत्नागिरि रिफाइनरी ऐंड पेट्रोकेमिकल्स के मुख्य कार्याधिकारी बी अशोक कहते हैं, 'हम रिफाइनरी का तकनीकी काम कर रहे हैं। हालांकि जमीन तय करना जरूरी है और हमारी नजर दो-तीन स्थानों पर है। सऊदी अरामको फिलहाल चल रहे कामकाज में पूरी तरह शामिल है।'

उद्योग जगत के एक अनुमान के मुताबिक बीपीसीएल के रिफाइनिंग क्षेत्र का मूल्य ही लगभग 400 डॉलर प्रति टन है जबकि शेष बुनियादी ढांचे में 200-300 डॉलर प्रति टन को और शामिल किया जा सकता है। इसमें टर्मिनल, पाइपलाइंस और खुदरा स्टोर आदि शामिल हैं। यह अनुमान एस्सार-रोसनेफ्ट के हालिया सौदे और एचपीसीएल की बाड़मेर रिफाइनरी की योजनाओं के आधार पर लगाया गया। बीपीसीएल को पेट्रोकेमिकल्स में ज्यादा अनुभव नहीं है। दूसरी ओर एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स उपक्रम स्थापित करने की लागत करीब 600-700 डॉलर प्रति टन आएगी।

आईओसी के पूर्व निदेशक (वित्त) ए के शर्मा कहते हैं, 'किसी भी विदेशी निवेशक के लिए बीपीसीएल एक आदर्श चयन है क्योंकि विपणन के देशव्यापी नेटवर्क के अलावा इससे तत्काल नकदी की आवक भी शुरू हो जाएगी। जबकि वेस्ट कोस्ट जैसी परियोजना शुरू करने में पांच से सात वर्ष का समय लग सकता है।'

मौजूदा बाजार हिस्सेदारी के अनुसार बीपीसीएल में 53.29 प्रतिशत सरकारी हिस्सेदारी की कीमत करीब 57,000 करोड़ रुपये होगी। इस पर यदि 20-30 प्रतिशत प्रीमियम जोड़ लिया जाए तो यह राशि 70,000 से 80,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है। आईजीएल और पेट्रोनेट जिनमें बीपीसीएल की हिस्सेदारी क्रमश: 22.5 फीसदी और 12.5 फीसदी है उन्हें भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि इससे मूल्य और बढ़ेगा।

बहुत संभव है कि खरीदार इस मूल्यांकन पर भुगतान न करें। पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑयल पीएसयू ऑफिसर्स और कन्फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र कंपनी ऑफिसर्स एसोएसिएशन जैसे अधिकारियों के संगठनों की मानें तो बीपीसीएल की परिसंपत्तियों का मूल्य करीब 9 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है।

उद्योग जगत के विशेषज्ञ अलग तरह से सोचते हैं। वैश्विक सलाहकार फर्म के एक अधिकारी ने कहा कि रूढ़िवादी तरीके से आकलन किया जाए तो बीपीसीएल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का स्थानापन्न मूल्य मिलेगा लेकिन एक नई रिफाइनरी अधिक लचीलापन प्रदान कर सकती है।

'नई बनाम मौजूदा' की यह बहस काफी समय से चल रही है और ज्यादातर यह सऊदी अरामको की भारत में निवेश करने की योजनाओं पर केंद्रित रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी कच्चा तेल उत्पादक कंपनी है। अप्रैल 2016 में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन खालिद अल फलीह से मुलाकात की और उनके सामने तीन पेशकश रखीं: वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी में साझेदारी, मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी के स्वामित्व और परिचालन वाले संयुक्त उपक्रम बीमा रिफाइनरी के विस्तार में भागीदारी या फिर दक्षिण-पश्चिम गुजरात में दहेज में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र। आरआईएल के पास यहां एक पेट्रोकेमिकल परिसर है।

आरआईएल के साथ अरामको का सौदा मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली इस कंपनी को कच्चा तेल जुटाने की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा और उसके सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) में सुधार करने में मदद मिलेगी। सौदे की शर्त के मुताबिक अरामको जामनगर रिफाइनरी को भी 25 एमटीपीए कच्चे तेल की आपूर्ति करेगा। इससे भी आरआईएल की कच्चा तेल हासिल करने की क्षमताएं मजबूत होंगी। यह उसे पारंपरिक रूप से भी अन्य प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाता रहा है। आपूर्ति की अतिरिक्त सुरक्षा के अलावा यह सौदा आरआईएल को मूल्य के मोर्चे पर भी बढ़त दिला सकता है क्योंकि एक अहम आपूर्तिकर्ता अब कारोबार में निवेशक भी होगा। इसका सकारात्मक असर पेट्रोकेमिकल्स कारोबार पर भी पड़ेगा जिसमें कच्चा तेल प्रमुख कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है। इससे आरआईएल को कच्चे तेल के वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं से भी निजात मिलेगी। यह अनिश्चितता अमेरिका और ईरान के बीच उपजे तनाव की वजह से है। यद्यपि एक असंबद्ध मामले के बकाये के चलते सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर इस सौदे को अवरुद्ध करने की मांग की गई है।

आरआईएल का सौदा और बीपीसीएल का आसन्न विनिवेश दोनों ने अरामको के लिए परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि एक विश्लेषक ने सुझाया इस महीने के आरंभ में वाल स्ट्रीट में आरंभिक पेशकश के चलते अरामको के पास इतना पैसा है कि वह इन तीनों सौदों पर आगे बढ़ सके।

इसके लिए पर्याप्त वजह मौजूद है। भारत अपनी जरूरत का 18 फीसदी कच्चा तेल सऊदी अरब से आयात करता है और इस उभरते बाजार में कंपनी को अपनी पहुंच मजबूत करने में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के समूह ओपेक के अनुमान के मुताबिक 2040 तक भारत की कच्चे तेल की मांग बढ़कर 58 लाख बैरल रोजाना हो जाएगी। यह वैश्विक चरणबद्ध वृद्धि का लगभग 40 फीसदी होगी। इस बात से समझा जा सकता है कि वैश्विक कारोबारी भारत में इस कदर रुचि क्यों ले रहे हैं?

चंद्रयान 3 अभियान को इसरो की हरी झंडी

बीएस संवाददाता/एजेंसियां

देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रमा के सतह पर पहुंचने के अपने पहले प्रयास में असफलता पाने के कुछ महीने बाद बुधवार को अपने तीसरे चंद्रयान अभियान को मंजूरी दे दी है। इसरो कम लागत वाली अंतरिक्ष ताकत बनने की महत्त्वाकांक्षा रखता है। इसरो के अध्यक्ष के शिवन ने बेंगलूरु के अपने मुख्यालय में कहा कि चंद्रयान 3 अभियान में एक लैंडर और रोवर होगा लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। सितंबर में चंद्रयान 2 अभियान में सफलतापूर्वक चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला ऑर्बिटर लगाया गया था जो धरती पर वैज्ञानिक आंकड़े जारी करता था लेकिन यह चंद्रमा की सतह पर रोवर को उतारने में असफल रहा।

इस अभियान के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की उतारना था जहां इससे पहले कोई दूसरा चंद्र अभियान पूरा नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में पानी क्रेटर में मौजूद है जो सूर्य के उच्च तापमान के बावजूद भी प्रभावित नहीं है। इसरो ने बर्फ के रूप में पानी की मौजदूगी की पुष्टि करने की उम्मीद की थी जिसका पता 2008 के अभियान में लगाया गया था।

गगनयान के लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है

शिवन ने बताया कि चंद्रयान 3 में भी पहले के अभियान जैसी ही समान चीजें हैं।

अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा के सतह पर उतरने में सफलता पाई है। पेइचिंग के चैंगई-4 प्रोब ने पिछले साल चंद्रमा के सुदूर हिस्से को छुआ था जबकि इजरायल ने अप्रैल 2019 में चंद्रमा पर अपने बीरेशीट अंतरिक्ष यान को उतारने की असफल कोशिश की थी।

परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह का हवाला देते हुए एक समाचार एजेंसी ने बताया कि देश के तीसरे चंद्रयान अभियान को 2020 में शुरू किया जाएगा और इसकी लागत पिछले अभियान की तुलना में कम होगी।

शिवन ने कहा कि इसरो अपने अंतरिक्ष यात्री वाले अभियान में अच्छी प्रगति कर रहा है जिसकी शुरुआत 2021 के आखिर में होगी और इसके लिए चार अंतरिक्षयात्रियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है और इस प्रशिक्षण की योजना इस महीने के आखिर में बनाई जाएगी। सरकार ने वर्ष 2018 में इस परियोजना को 'गगनयान' नाम दिया गया है जिसकी लागत 100 अरब रुपये से भी कम है।

देश ने किफायती उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष अभियानों के लिहाज से एक मुकाम हासिल किया है। इसके 2014 के मानवरहित मंगल अभियान की लागत 7.4 करोड़ डॉलर थी जो हॉलीवुड की अंतरिक्ष पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ग्रैविटी' की बजट की लागत से भी कम है। सिवन ने यह घोषणा की है कि इसरो ने तमिलनाडु के दक्षिणी बंदरगाह शहर तूतुकुड्डी में दूसरा स्पेसपोर्ट बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

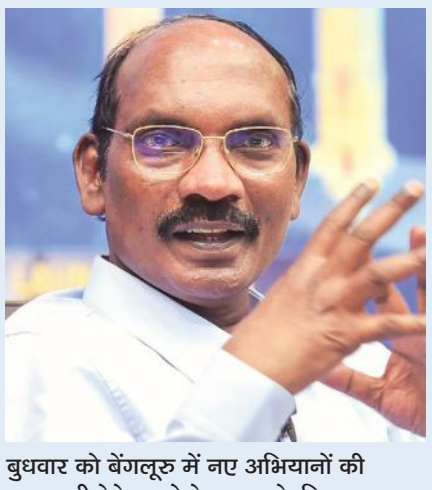

बुधवार को बेंगलूरु में नए अभियानों की जानकारी देते इसरो के प्रमुख के शिवन

सौर ऊर्जा पंप: चुनौतियों से जूझते किसान

हरियाणा, राजस्थान में खेती-किसानी से जुड़े जो लोग सौर संचालित पंप लेना चाहते हैं पर उन्हें कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। बता रही हैं **ज्योति मुकुल**

परबती लाल छोटू राम जाट ने अपने सिर पर परंपरागत पगड़ी बांधी हुई है और उन्हें देखकर ऐसा अंदाजा होता है कि वह ऐसे हठी इंसान होंगे जो किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहेंगे। सब्सिडी का लाभ लेने वाले दूसरे तबके के प्रति उनमें अजीब तरह का गुस्सा है। राजस्थान के सीकर में महरौली खटीक में रहने वाले जाट, बागवानी विभाग के अधिकारियों के एक समूह से कहते हैं, 'मैं आंदोलन से बच कर रहता हूं। जैविक खाता हूं और कभी बीमार नहीं पड़ता।' अधिकारियों का यह समूह उन्हें सौर ऊर्जा से संचालित पंप का इस्तेमाल करने के लिए आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी खेत की सिंचाई आसानी से हो सकती है, इसके लिए किसी को रात में जागना भी नहीं पड़ेगा और बिजली बिल की बचत भी होगी।

वह राज्य सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ पाने की पात्रता नहीं रखते हैं क्योंकि उनके दो बेटे सरकारी नौकरी में हैं और वे इस वक्त गुजरात में सीआईएसएफ के लिए काम करते हैं। हालांकि इसके बावजूद वह सौर संचालित पंप के लाभार्थी हो सकते हैं। जाट के तीन बेटों में से एक उनके खेत में उनकी मदद करते हैं और वह सिंचाई के लिए हर दो महीने में 1,800 रुपये खर्च करते हैं। उन्हें सिंचाई के लिए रोजाना छह घंटे की जल आपूर्ति की जाती है। वह अपने पड़ोसी शिशुपाल मीणा से बिल्कुल अलग हैं जिन्होंने एक पॉलीहाउस बनाने के साथ ही बारिश का पानी संग्रह करने के लिए तालाब बनाया है और उनके पास 5 हॉर्सपावर (एचपी) का सोलर पंप है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर जयपुर की तरफ उदयपुरिया है जहां हरि भगवान कुमावत अपने गांव की महिला पटवारी अधिकारी से काफी नाराज दिखते हैं। वह कहते हैं, 'यह तो सौर ऊर्जा की बात है न कि घरेलू बिजली की।' वह एक डीजल ट्रैक्टर की तरफ इशारा करते हैं जिससे एक पंप चल जाता है और खेतों में सिंचाई भी हो जाती है। पटवारी ही सौर ऊर्जा संचालित पंपों के लिए आवेदन को स्वीकृति देता है और उसकी एक शर्त यह है कि किसानों के पास ग्रिड कनेक्शन नहीं होना चाहिए या फिर पंपों को डीजल पर नहीं चलाया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार में प्रधान सचिव (बागवानी) नरेश पाल गंगवार कहते हैं कि केंद्र की कुसुम योजना के दूसरे अहम शर्त (कंपोनेंट सी) के मुताबिक सौर ऊर्जा पंप के लिए पात्रता रखने के लिए किसानों के पास सिंचाई के लिए ग्रिड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं, 'ग्रिड कनेक्शन वाले किसान जो सौर ऊर्जा वाले पंप चाहते हैं वे कुसुम के कंपोनेंट सी के तहत सरकारी सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।' उनका ही विभाग कंपोनेंट बी पर अमल कर रहा है जिसके तहत उन्हें अतिरिक्त 25,000 पंप लगाने हैं। राज्य के बजट में इसके लिए 257 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने जो पोर्टल सेट किया है उसके जरिये करीब 48,000 आवेदन मिले हैं। निदेशक (बागवानी) वी श्रवण कुमार कहते हैं, 'हम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 25,000 कनेक्शन दे रहे हैं।'

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के देरोली अहिर गांव के किसान एक घंटे के लिए पानी खरीदने के लिए 80-150 रुपये खर्च करते हैं। कुछ लोग जसवंत सिंह की तरह होते हैं जो पहले कुएं से पानी निकालकर उसका इस्तेमाल करते हैं हालांकि वे अब इसका कभी-कभार ही इस्तेमाल करते हैं। सिंह कहते हैं, 'दिसंबर और जनवरी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अच्छे नहीं हैं। भीषण गर्मी वाले मौसम में भी सोलर प्लेट्स से बिजली पैदा नहीं होती जब तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर लेता है। हमें पहले की व्यवस्था पर ही निर्भर रहना पड़ता है।'

हरियाणा कुसुम योजना के सभी तीनों हिस्सों को लागू करने जा रहा है और इसने पंपों के लिए सब्सिडी बढ़ाई है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य द्वारा 30-30 फीसदी सब्सिडी देने की अधिसूचना थी लेकिन हरियाणा अकेले ही 45 फीसदी सब्सिडी देगा। एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिये राज्य ने आवेदन मंगाए हैं और उन्हें 15,354 आवेदन मिले हैं। पहले चरण में कंपोनेंट बी के तहत इसे 15,000 पंपों की स्वीकृति मिली है।

महेंद्रगढ़ जिले के दफ्तर में 2019-20 के लिए आवेदनों की संख्या 1,000 के लक्ष्य के मुकाबले 819 है और यह कहा जा सकता है कि प्रतिक्रिया उतना उत्साहजनक नहीं है। जिले के 8 में से तीन ब्लॉक, नारनौल, निजामपुर, नांगल चौधरी में भूमिगत पानी निकालने की अनुमति नहीं मिली है और इसी वजह से आवेदनों की संख्या कम है।

कुमार के मुताबिक राजस्थान में 5-7.5 हॉर्स पावर सोलर पंप की मांग राजस्थान में ज्यादा है क्योंकि भूमिगत जल स्तर कम है। 3 हॉर्सपावर से भी कम क्षमता वाले पंप का इस्तेमाल केवल खेत के तालाब से पानी निकालने के लिए किया जाता है। हालांकि वह यह चेतावनी देते हैं कि ईईएसएल ने छह ठेकेदारों के नाम पर मुहर लगाई है ऐसे में पहले के मुकाबले अमल की रफ्तार धीमी रह सकती है क्योंकि तब 20 से अधिक ठेकेदार इस पर काम कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक ईईएसएल की निविदा में करीब 20 बोलीकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसमें 31 ने दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन छह अयोग्य साबित हुए और बाकी ने कोई वित्तीय बोली नहीं लगाई।

बोली लगाने वाले को पांच जोन में से चुना गया और पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दर ज्यादा थी। निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में देरी के बावजूद राज्य कुसुम की शुरुआत करने के लिए किसानों की तरफ से आवेदन मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

सौर पंप में बढ़ती दिलचस्पी: तुलनात्मक विश्लेषण

आवेदन	लक्ष्य
15,354 हरियाणा	15,000 हरियाणा
48,000 राजस्थान	25,000 राजस्थान

ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने की कोशिश

- हरियाणा ने यमुनानगर और करनाल में फीडर के साथ **468** पंप देने की पेशकश की है
- राजस्थान को **12,500** मौजूदा ग्रिड से जुड़े पंपों को सौर उर्जा से संचालित करना है

माइक्रो ग्रिड स्थापित करना

- हरियाणा ने **25** मेगावॉट का लक्ष्य रखा है
- राजस्थान को **325** मेगावॉट लक्ष्य के मुकाबले **6,314** मेगावॉट के लिए आवेदन मिल चुके हैं

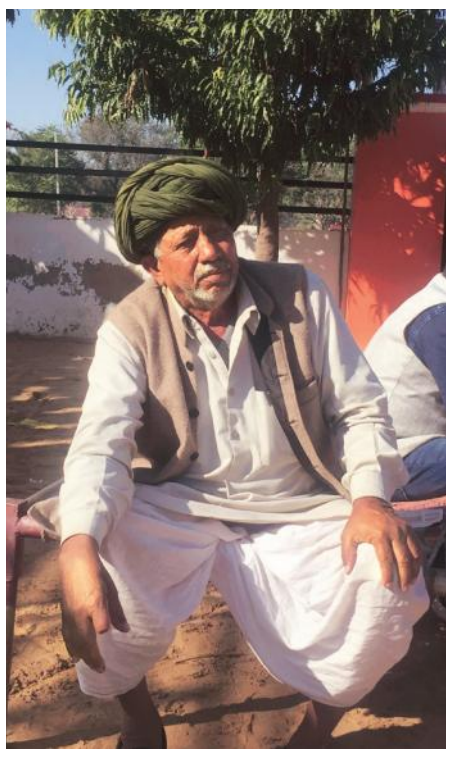

शिशुलाल मीणा (बाएं) ने पॉलिहाउस और तालाब बनाया है लेकिन परबतीलाल छोटू राम जाट खुद को बदलना नहीं चाहते

सूरज, पानी और मिट्टी
भाग-2

सरकार के निर्देश के अनुरूप करते हैं काम

जनरल बिपिन रावत

नव नियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र बल अपने आप को राजनीति से दूर रखते हैं और मौजूदा सरकार के निर्देशों के अनुरूप काम करते हैं। उनकी यह टिप्पणी उन आरोपों के बीच आई है कि सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। जनरल रावत ने यह भी कहा कि सीडीएस के तौर पर उनका लक्ष्य थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय और एक टीम की तरह काम करने पर केंद्रित होगा। सीडीएस उन पर नियंत्रण रखेगा लेकिन सम्मिलित काम के जरिये कार्रवाई की जाएगी।

अहम सुधार : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सैन्य मामलों का विभाग बनाना और सीडीएस पद को संस्थागत रूप देना अहम सुधार है। जनरल बिपिन रावत की सीडीएस के पद पर नियुक्ति पर उन्हें बधाई देते हुए मोदी ने कहा कि वह उत्कृष्ट अधिकारी है जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ भारत की सेवा की है।

चीन विवाद का समाधान

नए थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने उम्मीद जताई कि चीन से लगती भारतीय सीमा पर शांति के बरकरार रहने से सीमा विवाद का आंतरिक समाधान निकलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तरी सीमा पर सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'पहले पूरा ध्यान पाकिस्तान से लगती सीमा पर रहा है। चीन के साथ हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। सीमा संबंधी सवाल हल किया जाना बाकी है। हालांकि हमने सीमाओं पर शांति बनाए रखने में काफी प्रगति की है और सीमाओं पर शांति बरकरार रखकर हम समाधान के लिए मंच तैयार करने में सफल होंगे।' भारत-चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद है। *एजेंसियां*

साल 2019 में विज्ञापनों ने बदला कलेवर

कम अवधि के वीडियो, ऑडियो और दर्शकों को बेहतर अनुभव देने के तरीकों में बदलाव से पिछले साल विज्ञापन बाजार में कई तरह के बदलाव देखने को मिले

विवेट सुजन पिंटो

उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक बच्चे ने गूगल की वॉइस असिस्टेंट सेवा का उपयोग करके अपने पिता के लिए पटना जाने वाली ट्रेन की समयावधि को आसानी से देख लिया। वह इंटरनेट का उपयोग करने वाले ऐसे अनेक मोबाइल उपयोगकर्ताओं में से एक है जो आसानी से जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनका पूरा परिवार किसी भी समय गूगल असिस्टेंट का सहारा ले लेता है। इससे संबंधित विज्ञापनों का भी ग्राहकों पर काफी गहरा असर पड़ता है। वर्ष 2019 में पूरे साल डेटा, मोबाइल और तकनीक ने हमारी जिंदगी के साथ साथ विज्ञापन के नजरिये को भी बदल दिया है।

2019 ऐसा वर्ष रहा जहां ब्रांड ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्पादों में आवाज आधारित सुविधाएं जोड़ीं बल्कि इसे विशिष्ट बिक्री प्रस्ताव (यूएसपी) के तौर पर भी पेश किया। उदाहरण के लिए, एमजी मोटर्स ने साल 2019 में हेक्टर ब्रांड के साथ अपनी बहुप्रतीक्षित कार पेश की। इसमें आवाज की मदद से 90 से अधिक काम किए जा सकते हैं। यह विशेषता कंपनी की कार बिक्री के लिए आकर्षण का केंद्र बनी और अपने विज्ञापनों में एमजी मोटर्स ने अपनी टैगलाइन 'हैलो एमजी' का भरपूर इस्तेमाल किया। तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के लिए आवाज आधारित उपाय डेटा प्रसंस्करण के साथ और अधिक कारगर साबित हुए। उदाहरण के लिए, एमेजॉन ने न सिर्फ भारत में एलेक्सा स्पीकर लॉन्च किए बल्कि कंपनी की मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं में भी वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल किया। स्मार्टफोन ब्रांड ऐपल, सैमसंग, श्याओमी, ओप्पो और वीवो सभी में अपने-अपने वॉइस असिस्टेंट मौजूद हैं, जो इस साल कंपनियों के विज्ञापनों में दिखाए जाने वाली अहम विशेषता बनकर उभरे।

भारत में 82 फीसदी स्मार्टफोन यूजरों ने वॉयस एक्टिवेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया है

लाइफस्टाइल, ऑटो तथा फास्ट फूड विज्ञापनदाता जैसे डियाजियो, रॉयल एनफील्ड और केएफसी ने विज्ञापनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनमें वॉइस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया। हाइपर कलेक्टिव के संस्थापक तथा चीफ क्रियेटिव अधिकारी केवी श्रीधर कहते हैं कि भारत में बहुत से लोग लिखने के बजाय बोलने को वरीयता देते हैं। वह कहते हैं, 'भारत जैसे बहु-भाषीय देश में आवाज आधारित सेवाएं अच्छा काम कर सकती हैं। और अगर इन्हें बेहतर तरीके से समायोजित कर दिया जाए तो ये किसी भी ब्रांड के लिए शानदार उदाहरण पेश कर सकती हैं।' आई प्रॉस्पेक्ट द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में लगभग 82 प्रतिशत स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं ने किसी न किसी रूप में वॉयस-एक्टिवेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसमें व्हाट्सऐप पर टेक्स्ट टाइप करने के बजाय आसान तरीके से वॉयस मेसेज भेजना शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आवाज आधारित तकनीक की आवश्यकता दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ी है। जैसे कि गूगल पर संबंधित जानकारी खोजना या गूगल मैप का उपयोग करना।

जिस दौर में आवाज आधारित तकनीक कंपनियों के बीच अंतर करने के लिए अहम मानक बन गया है, वहीं छोटे वीडियो भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इसके लिए चीन की कंपनी टिकटॉक को भी सराहा जा सकता है जिसके भारत में 20 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं।

व्हाइट रिवर्स मीडिया के सह-संस्थापक और मुख्य कार्याधिकारी श्रीनिक गांधी कहते हैं, 'टिकटॉक ने भारत के छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को एक तरह की स्वतंत्रता दे दी है।' वह कहते हैं, 'इसके चलते कंपनी के उपयोगकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह केवल एख हिस्सा है, दूसरी ओर मोबाइल का उपयोग करने वाली जनता के लिए बहुतायत में उपलब्ध जानकारी का समुचित उपयोग करना जरूरी है। टिकटॉक ने इस विचार को अच्छी तरह प्रस्तुत किया है और 15 सेकंड का वीडियो कभी भी, कहीं भी देखा जा सकता है। इसके चलते ब्रांड इस फॉर्मेट को अपना रहे हैं।' हाल के महीनों में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट और पेप्सी, लेज़, क्लीन ऐंड क्लियर आदि ब्रांड अपने ग्राहकों को लाक्षित करने के लिए टिकटॉक का उपयोग कर रहे हैं।

विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ साथ इन रुझानों में भी इजाफा होगा। हरीश बिजूर कंसल्ट्स के मुख्य कार्याधिकारी हरीश बिजूर कहते हैं, 'कुछ साल पहले लंबी अवधि के वीडियो का चलन था। उस समय इतनी अधिक मात्रा में ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध नहीं थी। अब ऑनलाइन सामग्री बहुत अधिक हो गई है और ऐसे में छोटे फॉर्मेट वाली वीडियो कारगर होंगी।'

इस दौर में ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ा है और कुछ विशेषज्ञ इसके लिए अलग रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। कई ऑटो, फैशन और फर्नीचर ब्रांड ने अनुभव केंद्र स्थापित किए हैं जहां उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उत्पाद का वास्तविक अनुभव मिलता है। श्रीधर कहते हैं कि ब्रांड बेहतर अनुभव देने के लिए प्रयासरत हैं। वह कहते हैं, 'पहले विज्ञापनों ने ब्रांड के लिए बेहतर छवि निर्माण पर काम किया और अब अच्छा अनुभव देने के लिए काम कर रहे हैं।' उम्मीद है कि वर्ष 2020 में ये सभी एक बिंदु पर आकर समायोजित हो सकें।